Hyderabad, 83 acres in Amritsar and 17 acres in Lucknow, all these precious lands are under unauthorised occupation. These lands are worth crores of rupees.

These encroachments are source of bird attraction, which causes some amount of operational risk to aircraft and they also cause security concern at the airports.

The Government should set up a separate authority in this regard for rehabilitation of encroachments and setting of local disputes and take all follow-up actions where necessary with the help of State Governments concerned. The Government should also prepare proposals for commercial utilisation of such lands. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I want to take the sense of the House for adjourning for lunch.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, the House is adjourned for one hour for lunch.

The House then adjourned for lunch at eleven minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at eleven minutes past two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

GOVERNMENT BILL

The Electricity (Amendment) Bill, 2007

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we shall take up the Electricity (Amendment) Bill, 2007 for consideration.

THE MINISTER OF POWER (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Electricity Act, 2003 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration."

Sir, the power Sector is one of the most critical infrastructures for economic and social development. Reforms in the power sector have been

attracting greater attention in the last few years with a view to revive financial viability of the sector and to universalize access to electricity. Enactment of the Electricity Act, 2003 was one of the major reform initiatives taken by the Government. Provisions of the Electricity Act, 2003 have been generally welcomed by various stakeholders. The liberal and progressive framework for the power sector as provided by the Act has had a positive impact on the financial health of the utilities, investment in the sector and focus on consumer-related matters.

For considering the feedback received from the States, the National Common Minimum Programme of the UPA Government envisaged a review of the Act. This exercise has been done and the amendments to the Act now proposed are mainly for following up the review of the Act.

After its introduction in the Lok Sabha, the Amendment Bill was examined by the Standing Committee on Energy. A Group of Ministers also examined afresh the provisions relating to control of theft and unauthorized use of electricity. Government, after considering recommendations of the Standing Committee and those of the Group of Ministers, brought further amendments to the Bill. The Amendment Bill, as passed by the Lok Sabha, contains provisions for meeting the following objectives:

(i) It is proposed that the Central Government also shall, jointly with State Governments, endeavour to provide access to electricity to all areas including villages and hamlets through rural electricity infrastructure and electrification of households. Central Government has already launched the 'Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana' for supporting States in creating rural electricity infrastructure and electrification of households with the provision of 90 per cent capital subsidy to fulfill the objective of the NCMP of electrification of all households in next five years.

(ii) The Act presently provides for reduction and elimination of cross subsidies. Rationalisation of electricity tariff is essential for making the sector financially viable and for promoting energy efficiency. We have already prescribed a road-map for time-bound reduction of cross subsidies in the Tariff Policy. However, elimination of cross subsidies would not be feasible in the near future. Therefore, it is proposed to delete the provision of elimination of cross subsidies.

(iii) A number of amendments proposed in the Bill are being brought with the objective of further tightening the provisions for control of theft and unauthorized use of electricity. While formulating these amendments, we have also considered the experience and suggestions of various States particularly, West Bengal. Due care has been taken to ensure time-bound disposal of matters. To safeguard against harassment of the consumers, only the officers authorized either by the State Governments or State Regulatory Commissions will have powers to discontinue supply of electricity, etc.

(iv) One more amendment proposed in the Bill is to clarify that captive power plants are free to sell their surplus power without a license. This is required in view of a judicial pronouncement.

Sir, I now request the Hon'ble House to consider and pass the Electricity (Amendment) Bill, 2007 as passed by the Lok Sabha.

The question was proposed.

श्री अजय मारू (झारखंड): धन्यवाद उपसभापति जी। महोदय, मुझे विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2007 पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। उपसभापति महोदय, विद्युत विधेयक, 2003 जब तत्कालीन एनडीए सरकार के विद्युत मंत्री श्री अनंत गीते जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया था, तो उस वक्त भी मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया गया था। में उस समय ऊर्जा की स्थायी संसदीय समिति का सदस्य था और इसके अध यक्ष माननीय श्री संतोष मोहन देव जी थे और इस विधेयक को लाने के पूर्व हम लोगों ने विभिन्न राज्यों का इसके संदर्भ में दौरा किया था और जितने स्टेक होल्डर्स इस विद्युत बिल को लाने के संबंध । में थे, चाहे वह राज्य का विद्युत बोर्ड हो, चाहे केन्द्र की विद्युत उत्पादन की इकाइयां हों, चाहे कर्मचारी यूनियन हों, सभी की एक समग्र राय लेकर इसको बनाया था और उसके बाद वर्ष 2003 में इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित किया गया था। उस समय यह कहा जा रहा था कि विद्युत क्षेत्र में रिफॉर्म्स लाने के लिए जो बिल लाया गया है, यह देश के उत्थान के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा।

उपसभापति महोदय, उस वर्ष इस बिल का प्रमुख उद्देश्य था कि अगले पांच वर्षों में सभी को मांग के अनुसार बिजली दी जाये और उद्योग एवं सभी उपभोक्ताओं को पावर यानी विद्युत उचित मूल्य पर दी जाये और वर्ष 2012 तक प्रति व्यक्ति विद्युत का जो उपयोग है, उसको एक हजार किलोवाट तक किया जाये। महोदय, इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण बात ग्रामीण विद्युतीकरण

की थी। उस वक्त यानी 2003 में आजादी के 56 वर्ष बाद भी इस देश के एक लाख पच्चीस हजार गांव ऐसे थे, जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी। इस विधेयक के माध्यम से अगले पांच वर्षों के लिए टारगेट फिक्स किया गया था कि सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जाये। इसके अलावा राज्यों के जितने विद्युत बोर्ड हैं, उनका पुनर्गठन करके उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण के अलग-अलग बोर्ड स्थापित किये जायें।

उपसभापति महोदय, इन सभी कदमों को उठाने के लिए स्वाभाविक था कि वर्ष 2012 तक अतिरिक्त एक लाख मेगावाट बिजली की आवश्यकता महसूस की गयी थी। इस विधेयक के माध्यम से वर्ष 2011-12 तक जो एक लाख मेगावाट अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता महसूस की गयी थी, उसके लिए पांच लाख करोड़ रुपये की इस क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता महसूस की गयी और इस विधेयक के द्वारा निजी क्षेत्र एवं विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहन दिया गया था। यह संशोधन विधेयक अधिनियम, 2003 के कतिपय प्रावधानों में संशोधन करने के लिए लाया गया है, जिसका जिक्र मैं बाद में करूंगा।

उपसभापति महोदय, आज भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा बिजली उपभोग करने वाला देश है। अगर अमेरिका, चीन, रूस और जापान के बाद कोई स्थान है, तो वह भारत का है और ये पांचों देश मिलकर 51 प्रतिशत बिजली का उपयोग इस दुनिया में करते हैं। विशेषज्ञों का ऐसा अनुमान है कि आने वाले दस वर्षों में भारत का नम्बर तीसरे स्थान पर आ जाएगा यानी अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा ऐसा देश हो जाएगा जहां पर बिजली की आवश्यकता सबसे ज्यादा होगी। महोदय, आज हमारे देश में 1,29,082 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। ये आंकड़े 8 मार्च 2007 तक के हैं, जिसमें जल विद्युत की क्षमता 34,086 मेगावाट है यानी 26 प्रतिशत। ताप विद्युत जिसमें कोयला और गैस आते हैं, उसमें 84,905 मेगावाट है यानी 66 प्रतिशत। न्यूक्लीयर की जो हमारी क्षमता है, वह 3,900 मेगावाट है, यानी 3 प्रतिशत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत में 6,191 मेगावाट, यानी 5 प्रतिशत की है। महोदय, अगर हम 31 मार्च 2006 के आंकड़े लेते हैं तो हमारे देश में 1,24,287 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था। यानी एक वर्ष में हम मात्र 4000 मेगावाट बिजली अपने उत्पादन में बढ़ा पाए हैं। महोदय, आज जिस दर से हम औद्योगिक विकास कर रहे हैं, जिस दर से हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है - आज ही के समाचार-पत्रों में आया था कि इंडस्ट्री के क्षेत्र में हमारी विकास की दर 12 प्रतिशत से ऊपर हो गयी है - अगर यह विकास दर हमें जारी रखनी है तो विद्युत उत्पादन की जो विकास दर है, जो 4 प्रतिशत के करीब पिछले वर्ष और इस वर्ष आयी है, अगर यही दर रही तो हमारा जो लक्ष्य 2012 का 1,00,000 मेगावाट का है, वह हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए आवश्यकता है कि बिजली उत्पादन की जो दर, जो टारगेट हम फिक्स करते हैं, उसे हमें पूरा करना होगा। दसवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा विद्युत उत्पादन का जो लक्ष्य है, वह 41,110 मेगावाट रखा गया था, जिसमें हाइड्रो में 14,393 मेगावाट, ताप विद्युत में

25,417 मेगावाट और न्यूक्लीयर में 1300 मेगावाट का उत्पादन लक्ष्य रखा गया था। परन्तु महोदय, दसवीं पंचवर्षीय योजना में हम अपने टारगेट का सिर्फ 56 प्रतिशत ही बिजली का उत्पादन बढ़ा पाए हैं, यानी 23,250 मेगावाट ही हम पिछली पंचवर्षीय योजना में कर पाए जिसमें हाइडल में 8,186 मेगावाट, थर्मल में 13,664 मेगावाट और न्यूक्लीयर में 1400 मेगावाट कर पाए। अगर हम पिछली पंचवर्षीय योजनाओं को देखें तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो हमारा लक्ष्य 30,538 मेगावाट का था, उसमें से हम मात्र 54 प्रतिशत लक्ष्य को पूरा कर पाए, यानी 16,423 मेगावाट ही उत्पादन कर पाए। उसी तरह नौवीं पंचवर्षीय में विद्युत उत्पादन का जो लक्ष्य 40,245 मेगावाट का था, उसमें हम सिर्फ 19,015 मेगावाट, यानी 47 प्रतिशत ही लक्ष्य को पूरा कर पाए और जो दसवीं पंचवर्षीय योजना है, उसमें 56 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा कर पाए हैं। उसी तरह 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2007 से 2012 की है, उसका भी एक अति उत्साहवर्धक लक्ष्य 68,687 मेगावाट का रखा गया है जिसमें हाइड्रो में 15,585 मेगावाट, थर्मल में 50,124 मेगावाट और न्यूक्लीयर में 3,160 मेगावाट का है। परन्तु पूर्व की तीन पंचवर्षीय योजनाओं को अगर हम देखते हैं तो किसी भी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया है, उसकी तुलना में हम 50 से 56 प्रतिशत तक ही अपने लक्ष्य को पूरा कर पाए हैं। लेकिन अगर 2011-12 तक हमारी विद्युत की आवश्यकता को पूरा करना है तो इस निर्धारित लक्ष्य को हमें जरूर प्राप्त करना होगा, तभी हम बिजली की मांग के अनुसार उसे उपभोक्ताओं को और उद्योगों को दे पाएंगे। महोदय, एक अनुमान के हिसाब से वर्ष 2011-12 तक 9,75,222 मिलियन किलोवॉट बिजली की आवश्यकता हमें होगी। उसके लिए हमें 2 लाख 5 हज़ार मेगावॉट बिजली उत्पादन करना होगा। उसी तरह अगर 2016-17 का लक्ष्य हम देखते हैं, तो हमारी बिजली की आवश्यकता बढ़कर 1,32,000 मिलियन किलोवॉट हो जाएगी, जिसमें हमें 2 लाख 76 हज़ार मेगावॉट बिजली की आवश्यकता होगी। लेकिन महोदय, केंद्र सरकार जो अपने प्रोजैक्ट्स निर्धारित करती है, वे समय पर पूरे नहीं होते हैं। आज से सात साल पूर्व तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा झारखंड में, तंडवा में नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन के एक प्लांट की और बिहार में एन.टी.पी.सी. के कहलगांव में एक प्लांट की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन उसके बाद भी एन.टी.पी.सी. की तंडवा में जो योजना है, वह अधर में लटकी हुई है। वहां पर कोई काम आरंभ नहीं हुआ है, जबकि झारखंड एक ऐसा स्थान है, जहां से प्रतिदिन कई वैगन कोयला पंजाब के विद्युतघरों में, दिल्ली में आता है। अगर यही पॉवर प्लांट्स तंडवा में जो 2000 मेगावॉट का था, अगर वह उस समय आरंभ कर दिया जाता, तो जो कोयला हम रेल से दिल्ली लाते हैं। उसकी जगह पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन के द्वारा हम ट्रांसमिशन के द्वारा बिजली ला सकते थे, इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने जो प्रोजैक्ट्स हैं, उनको समय में पूरा करें, जिससे लागत भी कम होती है और समय पर हम लोगों को बिजली भी दे पाएंगे।

महोदय, इस समय हमारी पीक ऑवर्स में बिजली की जो आवश्यकता है, वह 1 लाख 403 मेगावॉट की है, लेकिन हमारे पास जितने साधन हैं, उससे हम 86 हज़ार मेगावॉट बिजली ही लोगों

को दे पाते हैं, यानी हम 14 से 16 प्रतिशत कम बिजली लोगों को दे रहे हैं। आज विश्व का जो सबसे बड़ा बिजली का उत्पादक है, वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। वहां पर साढ़े आठ लाख मेगावॉट बिजली का उत्पादन होता है, जिसमें साढ़े तीन लाख मेगावॉट करीब थर्मल से होता है, एक लाख मेगावॉट न्यूक्लीयर से होता है, साढ़े तीन लाख मेगावॉट गैस के द्वारा होता है और एक सौ मेगावॉट हाइड्रो के द्वारा होता है। अमेरिका जैसे देश में, summers के समय में जो बिजली की आवश्यकता होती है, वह सिर्फ साढ़े सात लाख मेगावॉट है। कहने का मतलब यह है कि वहां पर 20 प्रतिशत बिजली की क्षमता अधिक है और वह पीक के लिए भी अपनी बिजली की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं।

महोदय, आज विश्व में अगर हम प्रतिव्यक्ति बिजली की खपत देखते हैं, per capita बिजली का consumption क्या है, तो 209 देशों में भारत का स्थान 146वां है। अगर आइसलैंड को लेते हैं, तो वहां सबसे ज्यादा 26 हज़ार किलोवॉट प्रतिव्यक्ति बिजली की खपत है और अगर हम भारत को लेते हैं, तो 612 किलोवॉट प्रतिव्यक्ति बिजली की खपत हमारे देश में आज के दिन हो रही है और 2012 तक अगर हमें एक हजार किलोवॉट बिजली की खपत को ले जाना है, तो हमें बिजली का उत्पादन बढ़ाना होगा।

महोदय, अगर हम अपने विभिन्न प्रदेशों की बिजली की per capita consumption को देखें, उसमें दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है, जहां पर 1553 किलोवॉट बिजली की प्रति व्यक्ति खपत होती है, लेकिन वही अगर हम बिहार में देखें, तो बिहार में per capita बिजली का consumption मात्र 75 किलोवॉट है, और अगर मैं अपने प्रदेश को लेता हूं, तो वहां 546 किलोवॉट बिजली की खपत है। अगर हम 209 देशों का average लेते हैं, तो उनका भी औसत 3150 किलोवॉट आता है, इसलिए आवश्यकता यह है कि एक हजार किलोवॉट का जो लक्ष्य हमने 2011-12 के लिए रखा है, तो हमें अपने बिजली उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी करनी होगी।

महोदय, आज हमारे देश में भी जितने विद्युत उत्पादन के संयंत्र लगाए जा रहे हैं, वहां पर प्लांट लोड फैक्टर, जिसको पी.एल.एफ. कहते हैं, उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। जो हमारी installed capacity होती है, उस capacity के हिसाब से वहां के जो बिजली के उत्पादन संयंत्र हैं, वहां पर लोड फैक्टर काफी कम है। सन् 2006 में भारत के प्लांट्स में जो प्लांट लोड फैक्टर था, जो राज्य के विद्युत बोर्ड हैं, वहां पर 68 प्रतिशत था, जो केन्द्र के संयंत्र हैं, उनमें 81 था। जब हम निजी क्षेत्रों के संयंत्रों को देखते हैं, तो वहां पर 88 प्रतिशत देखते हैं। हम यह देख सकते हैं कि जो राज्यों के विद्युत बोर्ड हैं, और जो प्राइवेट सैक्टर के विद्युत बोर्ड हैं उनमें सिर्फ 20 प्रतिशत का अंतर है। इसलिए जो राज्यों के विद्युत संयंत्र हैं, उनमें केन्द्र के द्वारा राशि अधिक दी जाती है, सहायता अधिक दी जाती है, तो जो राज्यों के विद्युत बोर्ड हैं, उनके प्लांट लोड फैक्टर को बढ़ा दें, तो उन प्रदेशों में विद्युत की जो कमी है, वह पूरी की जा सकती है। आज कई ऐसे प्रदेश हैं, जैसे झारखंड है और

महाराष्ट्र जोकि उद्योग में सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां पर भी हर समय बिजली की कमी महसूस की जाती है। इनके अलावा मध्य प्रदेश है, तो इन सभी प्रदेशों में जो प्लांट लोड फैक्टर है, उसको हमें बढ़ाना होगा। महोदय, जिस तरह PLF है, उसी तरह T&D लॉसेस है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रिब्यूशन लॉसेस है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आज हमारे देश में T&D लॉसेस 31 प्रतिशत का है, जब हम अन्य देशों में देखते हैं तो चाइना में मात्र 7 प्रतिशत है, जापान में 4 प्रतिशत का है और अमेरिका में 6 प्रतिशत है। ये तो उन्नतिशील देश हैं, लेकिन यदि हम अपने पड़ोसी देशों को देखते हैं तो बांग्लादेश में यह मात्र 18 प्रतिशत है, श्रीलंका में 18 प्रतिशत है, नेपाल में 21 प्रतिशत है और पाकिस्तान में 26 प्रतिशत है जबकि हमारे देश में यह 31 प्रतिशत है। इसलिए राज्य सरकारों को T&D लॉसेस में सख्ती से कमी करनी होगी। महोदय, विद्युत अधिनियम, 2003 लम्बे विचार के बाद अस्तित्व में आया था और उम्मीद थी कि इस अधिनियम के लागू होने से विद्युत उत्पादन ट्रांसमिशन और वितरण के लिए राज्य बिद्युत बोर्ड का पुनर्गठन कर, इससे अलग-अलग बोर्डों में विभाजित कर दिया जाएगा। इससे प्लांट लोड फैक्टर और T&Dलॉसेस में भी कमी आएगी। महोदय, इसका परिणाम कई राज्यों में अच्छा निकला है। जिन-जिन राज्यों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है, उनमें प्लांट लोड फैक्टर और T&Dलॉसेस काफी कम हो गए हैं। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, जहां पर विद्युत बोर्डों को पुनर्गठन नहीं हुआ है। इनमें मेरा प्रदेश झारखंड भी है। जिन राज्यों ने विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया है, वहां पर बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं, लेकिन केन्द्र सरकार और विद्युत (ऊर्जा) मंत्रालय ने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, IIPA को राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन के प्रभाव का अध्ययन करने का एक कार्य सौंपा था, तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उस अध्ययन की रिपोर्ट आ गई है, अगर आ गई है तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, अगर उसकी रिपोर्ट नहीं आई है तो कब तक आएगी? यह भी बताने का कष्ट करें। महोदय, इस संशोधन विधेयक में ग्रामीण विद्युतीकरण की जिम्मेदारी केन्द्र और राज्य सरकार दोनों सरकारों को संयुक्त रूप से देने का प्रस्ताव है, यह अच्छी और स्वागतयोग्य बात है क्योंकि आज भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 44 प्रतिशत ऐसे घर हैं, जहां पर हम बिजली दे पाए हैं। आज भी देश के लगभग एक लाख से अधिक गांव ऐसे हैं, जहां पर बिजली नहीं पहुंची है। इसके साथ पांच ऐसे भी प्रदेश हैं, उनमें मेरा भी एक प्रदेश है, जहां पर 80 प्रतिशत गांव के घरों में बिजली नहीं है। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा कई अन्य प्रदेश हैं। महोदय, जहां तक मेरे प्रदेश झारखंड का सवाल है, वहां पर 29354 गांव हैं और आजादी के 60 साल बाद भी मात्र 9119 गांवों में बिजली पहुंची है और 20235 ऐसे गांव हैं, जिनमें बिजली नहीं पहुंची है। मैंने एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में झारखंड से ज्यादा ऐसे गांव हैं, जहां पर बिजली नहीं पहुंची है। उत्तर प्रदेश में काफी गांव हैं, लेकिन प्रतिशत के मामले में झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, जहां पर मात्र 30 प्रतिशत गांवों तक ही बिजली पहुंच पाई है। केन्द्र सरकार की जो योजना

है, उसमें केन्द्र से काफी पैसा उस प्रदेश में जा रहा है, लेकिन ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में वहां पर अभी भी काफी कमी है। मैं चाहूंगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में केन्द्र सरकार, जो 90% राशि दे रही है, इसका रिव्यू होना चाहिए। जो प्रदेश उस राशि का उपयोग ठीक से नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए।

महोदय, उम्मीद है कि संशोधन के बाद साढ़े सात करोड़ ग्रामीण घरों में तथा एक लाख से अधिक गांवों में अगले पांच-छह वर्षों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। इस संशोधन विधेयक में बिजली चोरी के मुदकमों के संबंध में भी कुछ प्रावधान रखे गए हैं। आज बिजली चोरी एक गंभीर समस्या है। राज्य विद्युत बोर्ड ने यह जानकारी दी है कि उनके द्वारा जो बिजली उपलब्ध होती है उसका मात्र सत्तर प्रतिशत ही बिल कर पाते हैं यानी तीस प्रतिशत ऐसा है जो या तो चोरी हो जाता है या ट्रांसमिशन लौस होता है। वे उसका बिल नहीं कर पाते हैं। एक तो तीस प्रतिशत का यह नुकसान होता है, दूसरा सत्तर प्रतिशत का जो बिल करते हैं, उस सत्तर प्रतिशत में मात्र 94% ही वसूल कर पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि राज्य के विद्युत बोड्र्स का दो तरफ से नुकसान हो रहा है। एक तो तीस प्रतिशत बिजली चोरी है। दूसरा जो वह बिल करते हैं, उसको पूरा वसूल नहीं कर पाते हैं। यह पांच, छह प्रतिशत का नुकसान हो रहा है। राज्य विद्युत बोर्ड को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

महोदय, मैं इन सब के लिए सिर्फ उपभोक्ताओं को जिम्मेदार ठहराने के पक्ष में नहीं हूं। बिना विभागीय मिली-भगत के इतने बड़े पैमाने पर बिजली चोरी संभव नहीं है। इसलिए सिर्फ उपभोक्ताओं को दोषी मानकर कार्रवाई करना उचित नहीं है। इस सबका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बिजली चोरी के प्रावधानों का उपयोग उपभोक्ताओं को डराने, धमकाने अथवा ब्लैकमेलिंग के लिए न हो। संशोधन विधेयक में कहा गया है कि केन्द्र सरकार अथवा किसी उपयुक्त आयोग अथवा मुख्य विद्युत निरीक्षक की अनुमति के बिना किसी उपभोक्ता पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह एक स्वागतयोग्य कदम है। उपभोक्ताओं के खिलाफ जांच-पड़ताल अथवा मुकदमा चलाने की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी निर्दोष को परेशान न होना पड़े।

जहां तक बिजली चोरी के मामलों को निबटाने के लिए विशेष अदालतों को गठित करने का प्रस्ताव है, मैं इसका समर्थन करता हूं। सिर्फ विशेष अदालतें गठित करना पर्याप्त नहीं होगा। प्रयास यह होना चाहिए कि विशेष अदालतों के माध्यम से जो भी मुकदमा है, उसका यथाशीघ्र एक निश्चित अवधि में निबटारा होना चाहिए।

महोदय, अभी आपने कैप्टिव पॉवर प्लांट की एक बात इस विधेयक में कही है। यह भी एक स्वागतयोग्य कदम है। कैप्टिव पॉवर प्लांट लगाने के बाद जो प्राइवेट ऑपरेटर्स होते थे, उनमें यह शक होता था, शंका होती थी कि अगर वे बिजली उत्पादन को विद्युत बोर्ड के माध्यम से बेचेंगे तो

उनकी राशि का तुरंत भुगतान नहीं होगा। इस अमेंडमेंट में आपने जो एक क्लॉज दी है कि वे अपने उत्पादन को निजी क्षेत्र में भी बेच सकते हैं, यह एक स्वागतयोग्य कदम है। इन सब बातों के साथ मैं कुल मिलाकर इस विद्युत संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं आपने मुझे जो समय दिया है, उसके लिए आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak. Sir, first of all, I congratulate the UPA Government particularly the hon. Minister, Shri Shindeji, for moving this amendment to Section 6 which actually shows the aam aadami's need and also the focus upon the aam aadami, but at the same time, Sir, Cooperation of the State Governments is also very much needed for this. The Central Government has already made a provision of more than Rs. 16,000 crores for subsidy to different areas of India. But many of the State Electricity Boards are not coming forward with the reforms, that is, the management and also the administration has to be changed. But they are running in the same way, which was already causing loss to every State Electricity Board. I would like to attract the attention of the Government to the fact that we are encouraging the private sector to flourish; we need not worry about the electricity being given to them in a regulated way. When they are investing money and when we are allowing through the Electricity Act, 2003 that anybody can produce electricity for that purpose, with the permission of the Government, then we have to say that when a person is investing huge money for their industry or for any venture they have to look after their own necessity of electricity also, especially the sugar mills. If you take the sugar mills, the sugar price, the cane sugar, the cane price fixed for the agriculturists is not having the component of the production of the electricity and selling of electricity. The agriculturists are getting only an amount, which is already fixed, which is about Rs. 1000 or so. But this is given only for the purpose of sugar. But the molasses is used for the purpose of generating electricity. They are earning money by selling it at a huge cost to the local Electricity Baord but they are not compounding that money along with the price of cane. Therefore, the agriculturists are totally taken away. We can even use the words, "he has stolen away that price which is owed to the agriculturists." Therefore, Sir, when the right to sell it to anybody else is given to the sugar mills, then they should have the obligation. At least certain percentage of 30 per cent or 50 per cent of generated electricity

should be given to the agriculturists free of cost. This type of condition should be imposed. Otherwise, they are generating very cheaply without any further investment. They are earning the money by selling in multiples to the electricity board. Then the Electricity Board in turn sells it to somebody else for lesser money. This vicious circle has to be broken. Therefore, when we are calculating that so much electricity is produced through the thermal power or atomic power or hydel power, we have to catch up with the status which is already fixed by the World Bank or by US. But at the same time, we have to think about our people. As Lenin said, 'Electricity is a thing which makes a revolution of Russia'. Therefore, electricity has not reached the villages of India even after 60 years. It has to reach the villages and it has to reach every cottage. We have seen in yesterday's paper that in the UPSC examination, an OBC candidate, a son of a fisherman could become a topper at the All India level. Being a fisherman's son, he has suffered a lot to prepare himself for the UPSC examination but whether he has got electricity or not we do not know. At the same time, many of the people have got the potentiality to come up. They are in a scarcity of getting minimum requirement of water and also electricity and shelter. These things should be combined together and there should be a programme as already envisaged by the National Health Mission and also the Rural Health Mission. We have to see that electricity is also part of it Electricity should reach the hamlets. It was a very well framed command. I can even say that by reading the provision, I feel that the Government's intention can be very easily seen. Amended Clause 6 says, "the concerned State Governments and the Central Government shall jointly endeavour to provide access to electricity to all areas including villages and hamlets through electricity infrastructure and electrification of households". This is the aim of UPA Government. This has to be achieved. This has to be achieved even though this enactment has been brought in. It is a well made amendment and at the same time, Sir, many of the elimination clauses are also well made because I was also a party to it when this law was originally floated in Lok Sabha in 2003, when I was a Member of Lok Sabha. At that time we could also warn the Government that gradually you are making all subsidiaries and also the programmes for the poor people to be eliminated. You are under the command of the World Bank. World Bank has imposed certain things, therefore you are doing like this. The same thing is now taken away. Therefore we congratulate the Government that they are thinking about the people, actually the rural people. Sir, I

would like to mention here another important thing. When the generation of electricity is in the hands of private sector, we have to regulate it. It is because, you know very well, the electricity management system in the country under public sector is very old. As a result, one can very easily steal power. As a lawyer, and we all know very well how poor people are prosecuted everyday and how rich people, who are stealing power every day in Delhi, etc.. go scot-free. The rich people are earning a lot by stealing power. They are putting wires on high-tension wires/poles, steal power and are even running factories! Nobody is finding them as accused under the Electricity Act. Therefore, the system of supervision, the system of monitoring and the system of prosecution should be strengthened. It should not be done in a casual way as it is being done by States. That has to be regulated and the Central Government has though it does not have much power under this Act to make them aware that the electricity is for the common man's development, and the rich man has no right to steal power in any manner. But, at the same time, when Smt. Indira Gandhi was having the ambition to bring atomic energy, we were very happy. The Southern India is very much benefited from this. It has given a very good scope for the development of industries in South India. But at the same time, the load shedding is creating problems in villages. Even though 24 hours power is available in Tamil Nadu in other Southern States, the villages are not really getting the benefit. In Tamil Nadu free power is given for agriculture. But the agtriculturists are not getting power to pump water from wells. They are not getting it for 24 hours due to load-shedding. In the name of load-shedding, they stop for six to seven hours. Therefore, the agriculture production is also suffering. We have to focus upon the electricity *vis-a-vis* development of agriculture production. When the Government gives power at a subsidized rate, it has to look at other aspects as well. The proposed amendment says, 'houses and hamlets to be electrified.' That purpose is necessary, because we are not achieving the target at the all India level. Even in States like Uttar Pradesh, Bihar and Chhattisgarh 60 per cent of people are not getting power. In Tamil Nadu, 99 per cent of people are getting power. But at the same time, in other States, they have to achieve it. Whatever they have produced has to reach the hamlets and villages. They should also concentrate on giving power to agriculturists. If they give power to agriculturists, at free of cost, in the entire country, the prices of rice, wheat and on other things will come down. So, I appeal to the Government of India that expenditure incurred by agriculturists should also be

borne by the Government. Therefore, I am very happy that the Government has come forward with this amendment.

Sir, I would like to add one more point here. Sir, solar energy, biogas and tidal energy are also not fully tapped by India. I would say, especially solar energy has not been utilized full by us. I read an article in a newspaper that in China every building should have solar energy. It has been made compulsory. When we go in for solar energy at village level, the cost of installation is very high. Therefore, I propose subsidizing this totally by the Government. Or, there should be mass installation of solar energy panels, so that we can electrify villages and the same can be utilized for pumping of water. Therefore, I feel, natural products such as biogas, molasses, etc., have to reach villages from where they have come and these could be utilized in cities. At the same time, we want development of cities and modern inudustries. The modern industries, you know very well, need a lot of electricity. We have to tell them that when they start a new industry, they should see that electricity, water and other things should be looked after by themselves and the Municipality or State Government should not be burdened. They should be told to serve the commonman and poor people. Thank you.

श्री वीरेन्द्र भाटिया (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2007 का समर्थन करता हूं। मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने अभी बहुत सी बातें कही, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। डा॰ नाच्चीयप्पन जी ने अभी कहा कि पानी, बिजली और मकान एक मनुष्य के जीवनयापन के लिए आधारभूत आवश्यकताएं हैं और ये सस्ते दर पर साधारण और गरीब नागरिक को अवश्य मिलनी चाहिए। इस बिल की भावना इसी प्रकार की लगती है, इसलिए यह स्वागत योग्य है। इस बिल में यह भी कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, दोनों ही सहयोग से कार्य करेंगे, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिस भावना से यह कहा गया है, वह भावना यथार्थ रूप में परिणत की जानी चाहिए, क्योंकि हमें बड़ा कटु अनुभव है। जब उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले तक हमारे मुलायम सिंह जी की सरकार थी, जब विद्युत उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रयास किए गए, तो केन्द्र सरकार उसमें बाधक बनी, समर्थक नहीं बनी। मैं समझता हूं कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। महोदय, बार-बार कहने के बाद भी गैस सप्लाई नहीं की गई, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं आशावान हूं कि भविष्य में अगर केन्द्र में राज्य की विरोधी सरकार भी होगी, तो उसका भी सहयोग किया जाएगा, क्योंकि जो उस राज्य में रहने वाला नागरिक है, वह भी भारत का नागरिक है और सबको एक दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

महोदय, बहुत सी बातें कही गईं, मैं समझता हूं कि उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि गरीबों को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिए- एक पंखा, दो पंखा, दो ट्यूबलाइट्स जो उनकी आधारभूत आवश्यकता है, उसके लिए भी उन्हें आज इतना बिल देना पड़ता है कि एक गरीब व्यक्ति, वेतनभोगी व्यक्ति और लोअर क्लास के व्यक्ति को उसे afford करना मुश्किल होता है। इसलिए कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो गरीब तबका है, उसके लिए tariff कम होनी चाहिए जिससे उस व्यक्ति पर इसका अतिरिक्त बोझ न पड़े। महोदय, आज गरीब व्यक्ति महंगाई व खाद्यान्नों की महंगाई के बोझ को सह नहीं पा रहा है, उस पर जब बिजली के बिल का बोझ भी पड़ता है तो वह टूट सा जाता है। यह उनके लिए बहुत आवश्यक है, अतः इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस बिल के अमेंडमेंट में कुछ ambiguity है, vaguencess है जिसका फायदा अभियुक्तों को मिल सकता है। आप कृपया अमेंडमेंट 8 को देखें। For section 155 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely, "no prosectution shall be instituted against any person for any offence, punishable under this Act, except at the instance of the appropriate Government or appropriate Commission or any of their officer authorised by them or a Chief Electrical Inspector or an Electrical Inspector or licensee of the generating company, as the case may be." What will be the definition of 'instance'? 'Instance' को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। यहीं पर मैं अपने को एक वकील के रूप में रखता हूं तो 'Instance' के रूप में क्या परिस्थिति होगी? 'Instance' यह भी हो सकता है कि orally कह दिया गया कि आप वहां पर जाकर छापा मार दीजिए और prosectution launch कर दीजिए। क्या यह 'Instance' होगा? और इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा अभियुक्त को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर, दूसरे पैरा में आपने कह दिया है - "Provided that the court may also take cognizance of an offence punishable under this Act upon a complaint in writing. By amendment in 151(1) you said, 'at the instance of ', and then, you say in 3, "the cognizance of offence under this Act shall not in any way prejudice any action under the provisions of the Indian Penal Code, and, simultaneously, provided that the court may also take cognizance of the offence punishable under this Act upon a complaint in writing." दोनों में थोड़ा-सा विरोधाभास है। एक तरफ 'Instance' और दूसरी तरफ 'May also take complaint in writing made by the appropriate Government or appropriate Commission or by any of their officer authorized by them or a Chief Electrical Inspector or an Electrical Inspector or licensee or the generating company as the

case may be. "When will that be applied and when will this be applied? If you say that one will be applied at the pre-cognizance stage, it cannot be, because you say that the prosecution shall be launched. Why have these different paragraphs been inserted, and why the instance has not been defined? This is the ambiguity. जिसकी वजह से अभियुक्त को फायदा हो सकता है। दूसरी बात, आप यह कह रहे हैं कि No prosecution shall be launched except on a written complaint.' You have made the offence cognizable. You have said that the investigation will be conducted by the police in accordance with the procedure of the Cr. PC. You are saying, "For the purpose of investigation of any offence punishable under this Act, the police shall have the powers as available under the Code of Criminal Procedure, 1973." On what basis will the Agency investigate? At both the places, you have used the word, 'prosecution'. And the prosecution starts after the charge sheet is filed or the complaint is filed. It should have been that the investigation should have been made on the basis of the FIR. That is the ambiguity left in this amendment. You have not taken care of those cases where the FIR is lodged. And, can the FIR be lodged? The question arises, after this, can any action be taken on the basis of the FIR? What will happen? Has the police been given the powers to lodge the FIR and to investigate the matter? Because of this ambiguity the benefit may go to the accused persons.

The third point is this. You have said that the offences will be tried by the special court. The offence means the offences under the Electricity Act. And, then, you have also said that the cognizance of the offences under this Act shall not in any way prejudice any action under the provisions of the Indian Penal Code. That is right. But I want to know whether along with the offences under the Electricity Act, certain other offences are made out under the provisions of the Indian Penal Code. You have not specifically mentioned it here as mentioned in other Acts that along with these offences the special court has the powers to try the offences relating to the IPC offences. That should be there. Otherwise, you say that theft is an offence under the provisions of the Electricity Act. And theft also can be an offence under the provisions of section 379 of IPC. What will happen to those offences under section 379? Whether the special court can try those offences along with IPC offences or not, that has not been mentioned here. It should have been that the special court will have the powers to try the offences under the IPC along with the offences under the

Electricity Act. Because under section 379, the offences are triable by the Magistrate. (*Time-bell*) Here, the offences are triable by the Session Court. Hence, both should be tried by the special court. This is number one.

3.00 P.M.

Then, Sir, section 152 of the Act deals with compounding of the offence. Let me read it out. Section 152 says "the acceptance of a sum of money for compounding an offence in accordance with the sub-section 1 by the appropriate Government or an officer empowered in this behalf shall be deemed to amount to an acquittal", then, you are right in saying that notwithstanding section 379, offence may be there, but then, it will be argued from the accused side. Being a lawyer, I can argue that whether the principal of double jeopardy will not apply in that case. For the same act or omission, for the same offence, you are being tried one under the provisions of the Electricity Act and another under the provision of section, 379 and when you are discharging one case, whether the accused cannot seek shelter under section 300 Cr. PC.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI VIRENDRA BHATIA: That is the question to be considered by you. Sir, this is the ambiguity and that may make this amendment redundant and it may be used for the benefit of the accused. With these words, I thank you and support the Bill.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Hon. Deputy Chairman, Sir, I would like to express some of my serious concerns on some of the aspects of the Bill while welcoming some other aspects. It is a mixed bag, in my perception. Sir, in the National Common Minimum Programme, they have committed for a thorough review of the Electricity Act, 2003. If we construe that Electricity (Amendment) Bill, 2007, is a product of that review, then, I think, I am frustrated over the kind of review that has been made. In my view, the basic plank of the Electricity Act, 2003, was unbundling, dismantling, corporatisation and privatisation steadily to enthuse all round initiative in the power sector. In fact, the process of unbundling, dismantling, corporatisation and privatisation started well before the Act was enacted, possibly from 1998 or 1999 onwards. Today, the situation is there to see what the result is. Sir, the CRISIL, ICRA, had made some studies. As per their studies and the rating made by them out of the six

State power utilities in terms of efficiency, improvement of AT & C losses, improvement of performance etc. five SEBs are in those States which were till 2004 not unbundled. That is the way they responded to the kind or reorganisation prescribed by the Electricity Act, 2003. If a review of this development is made, then. I think the Electricity (Amendment) Bill, 2007 would have brought forth certain other important issues, required issues which are not present in this Bill. So, my first complaint is that the review has not been made in an objective manner, which is really to give a right direction to the country's power situation.

Secondly, Sir, I would like to point out that this Bill which has been brought here has made certain amendments to certain provisions which are welcome. Let me start with the welcome provisions. Sir, a tightening measure has been introduced about the theft. It is a welcome step. But, at the same time, I will request the hon. Minister to consider one thing. While defining theft, the unauthorised usage is also included in theft. I think, it is not a correct approach. As you have seen, the theft and the authorised usage should not be construed as one and the same thing. There are various procedures of recovering the dues, disconnecting lines, etc. There are also so many other things. But the manner in which the measures have been suggested in the Amendment Bill to tackle the theft, I think, is not correct, if the unauthorised usage is also included in that, a segment of persons who are involved in that will be subjected to such harsh measures, which they do not deserve. One is the administrative default and another is a deliberate crime. Definitely, the crime should be handled in a very stringent manner, but, at the same time, the default should not be tackled in the same parameter as crime. So, I request the hon. Minister to reconsider that area so that the theft is properly defined, removing the default part from it.

Thirdly, Sir, I am quite apprehensive about the provision that has been made regarding captive generation. I think, it is going to create a serious problem. Some of my friends have welcomed it, but I conceive a serious problem is going to come in, particularly, when in the power sector, the private power producers are also being encouraged. I will also create a serious problem for the Regulator. Anybody as captive power generator in a particular corner of the country can demand the power being produced to be wheeled to them through the open access to the general transmission line and, without attaining a licence, he will be having his business on

power, just claiming that I am a captive power generator for ten other group of industries. I think, it will create a serious anomaly in the power and electricity administration of the country and, definitely, in the larger interest, will not be beneficial either to the general power administration or to the common people, except allowing some big bang gains for a few private operators. This is alarming, particularly, when, as a matter of policy, the Government is encouraging more and more private operators. They need a Regulator; they need proper regulation, not a kind of licence-free raj to them. So, I think, that is an important case to be addressed. I request the hon. Minister to totally review and revise this provision so far as the captive generation part is concerned. Who are captive, they must remain captive. If a steel plant is having a captive power plant, let them cater to that steel plant, and if they are to cater their excess power to others, let them come through licences and let them do it through the State power utilities by paying the required service charges. I think, that should be the idea. Without getting the licence, they should not be allowed that kind of liberty.

Fourthly, Sir, I welcome the provision for elimination of the word 'elimination' of cross subisdy. While placing the Bill for the consideration of the House, the non. Minister mentioned about the elimination of 'cross subsidy'. That word is taken away. But it was replaced by the word 'reduction'. I do not want to go on debating on this. Our society requires cross subsidy. Sir, at present the economic level of our society is such that subsidy should not be construed as an obscence concept. When 2.3 lakh crores of rupees revenue has been forgone, as declared in our Budget, it means it is subsidising of the few by million of commoners. When there are Rs. 1.2 lakh crores of unpaid tax arrears, a substantial part of which is indisputable but still remaining as arrear for years together, that again means a subsidy by millions of common people to the few biggies in the society; subsidy should not be construed as an obscene concept. Cross-subsidy must continue. Replacement of the word 'elimination' by 'reduction', no doubt, is a improvement, but the hon. Minister must assure that that reduction should not finally lead to elimination because there is every reason to have that kind of an apprehension in the minds of the common people of the country. I personally know how much people have mobilised themselves throughout the country to ensure the inclusion of the expression 'review of the Electricity Act' in the NCMP and the retention of the cross subsidy. So, I would request the hon. Minister to kindly ensure, through his reply, that reduction does not ultimately lead to elimination.

Sir, I welcome the Central Government's cooperation in rural electrification. But, at the same time, I would like the hon. Minister to kindly consider the view that that area also needs to be clearly defined. The area of cooperation, the job, the tasks involved, the authority, and so on must be clearly defined so that there are no conflicts of interest and there is no mutual blame-game which ultimately results in nothing. It is very important that that is clearly defined. Secondly, the Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana provides for 90 per cent capital subsidy for rural electrification, which is a welcome step. But, unfortunately, that creates an apprehension about this conflict of authority and interest. It was tied with the conditionality of introducing a franchise system. I think most of the State Governments are opposed to that kind of a concept of franchise. You are providing monetary assistance for rural electrification. That is a welcome step. But, don't tie up with that condition; let the State power utilities decide how they would administer it. You must only monitor the result — how much area they could cover, how much losses they could contain, how much revenue they could collect, etc. You may monitor the results, but you must leave the modalities of collecting revenue and other things to the State Governments; that would be the real spirit of cooperation. Hence, I would urge upon the hon. Minister not to make franchise as a conditionality for the Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana.

Sir, I would make one last point and conclude my speech. Cost of power is one aspect on which I would like to seek some clarification from the hon. Minister. All necessary steps should be taken to make electricity available to all at an affordable price. The situation is that post Electricity Act, 2003, the cost of power has been increasing at a very fast pace, particularly in the States which went ahead with the dismantling exercise. The Chief Minister of Delhi had herself said that private distribution could not deliver the results. Now, what is the situation of power cuts? I would not go into all that. But I wish to draw your attention to a few facts.

The NTPC is the biggest provider of power in the country; it is biggest producer and generator of power. Now, Government has launched an ambitious programme of ultra mega power projects of 4000 MW; five projects have been planned. In the Sasan Project, NTPC being the leading power generator, has quoted Rs. 2.47 per unit *vis-a-vis* the lowest quotation of Rs. 1.19 by Lanco. In reply to a question in this House, and in a subsequent clarification given by the hon. Minister to me, he had quoted that

NTPC's production cost was Rs. 1.32 to Rs. 1.33 per unit for smaller projects of 210 or 250 MW. For 8000 megawatt project, according to the economy of scale, the cost should have been much less. Still, instead of quoting less than Rs. 1.33, quotation was given above Rs. 2, much above Rs. 1.19. Has it been done by NTPC management under its own prudence or they have done it under the direction of the Power Ministry? If they have done it of their own to allow private operators to have a cakewalk in the project, I think, they have to be called and seriously pulled and their integrity has to be questioned. If they have done it under the direction of the Ministry, the Ministry should clarify whether it is the policy of the Government to allow the private operators to have a free cakewalk in the area of ultra mega power projects. At least, this economics of quoting *vis-a-vis* power unit cost brings forth this basic question, and this basic question is equally related to making power cheap and making cheaper power available to mass of the people. Then I think this House owes an answer to this basic question. With this, I again request the hon. Minister to kindly reconsider the areas of captive power generation problem, the definition of theft *vis-a-vis* unauthorised usage and also reconsider and give an assurance to this House that cross subsidy, however improbable it is, is subject to reduction, but not be pushed to final elimination because in the present society, in any equitable society, a differential treatment to people of differential economic position is called equity and that is the definition of the equity. If we claim our society to be an equitable one, cross subsidy must continue, must continue to continue even in the power utility sector.

SHRIMATI S.G. INDIRA (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. On seeing the Electricity Amendment Bill, 2007, the first amendment is in Section 6 of the Act which speaks about the appropriate Government which is responsible for electrification in the rural areas. The Central Government is always supporting the rural electrification through budgetary provision and through instruments like rural electrification cooperation. Sir, now, we are talking about rural electrification. But there is a shortage of electricity in every State. So, we have to be concerned about that and we should take care of this shortage. Sir, the Government is in a position to provide electricity to consumers. Now, we are talking about the State Governments and Central Government's joint responsibility in the rural electrification. But before that, we should think about the quality of the electricity and we should not put more burden on the already over-

burdened present infrastructure. My second point is regarding reliability. In most States, there are unannounced power cuts for more than five or six hours. It is prevailing in Tamil Nadu. Unannounced power cuts affect the domestic consumers. So, we should also take care of the reliability.

[THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair]

My third point is regarding affordability. We should think as to how we can maintain these three things. If we take care of these things, only after that we should think about rural electrification. Just putting the Electricity Bill will not help the rural poor. So, all these things should be taken care of and benefits should reach the poor people.

Next issue relates to cross-subsidisation. We should balance it among the more-paying consumers and the less-paying consumers. We should not ignore the industries because they are the more-paying consumers of the Electricity Boards. Sir, at the same time, I am not opposing giving subsidy to the agriculture sector or the poor people. The Government should balance both the sectors. This new amendment talks about subsidy. It is a welcome step, but it must be done in a transparent manner, that is, the State Government giving the subsidy to the utility by a transfer of amount which is equivalent to the difference between the tariff, that is fixed, and the amount of subsidy which the Government wants to give. So, this should be done in a transparent manner. Then, I would like to say that the poor agriculturist should get power at a subsidised rate, but, at the same time, we should not ignore the industries which are paying more to the Electricity Boards because they are also creating employment by providing jobs to the workers who are working there and earning their livelihood. So, both should be provided subsidies in a balanced manner.

The other point is regarding theft. It is a very serious problem and it should be prevented at the earliest. The Government is losing crores and crores of rupees due to electricity theft. Theft of electricity should be treated as a cognisable offence. The Government can curtail this menace in many ways. Sir, theft takes place due to lack of accountability. There can be a provision whereby the Government should take the responsibility regarding distribution, and persons liable for theft should be punished. It is a serious thing that they are going to jail and again, they come out and they do the same thing again and again. So, the Government should have a

proper mechanism and the culprits should be punished severely. It is a great loss to the Government. So, it should be seriously taken care of. Some technological measures can also be taken to avoid the electricity theft. Opinion of experts can also be taken on how to avoid it.

Again, one more thing, which is not in the Amendment, is regarding increasing generation of e-waste, which is not utilised. In this connection, I would like to draw the attention of the Government to establish a separate authority which will make laws and regulations for the safe disposal of e-waste in our country to avoid environmental disaster. At least, in the years to come, measures should be taken in this regard.

Then, I would like to say that we have to give importance to the captive power generation. In some States, they are not providing the power to the consumers and also they are not encouraging the captive power generation. So, the State Governments, jointly with the Central Government, should encourage the captive power generation plants.

Finally, Sir, there is one more welcome provision in this Bill, that is, 'open access'. Only then, we can get more and more power generation and will be able to help the poor people. So, when we are providing the electrification in rural areas, we should take care that it is affordable, and without any shortage, we should provide electricity to the poor people and to the agriculture sector. With these words, I welcome this Bill.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. I rise to support the Electricity (Amendment) Bill, 2007. Before I go into the details, I just quote Lord Macaulay's address to the British Parliament on 2nd February, 1835. This is a historical comment and I quote, "I have travelled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such calibre, that I do not think we would ever conquer this country, unless we break the very backbone of this nation which is her spiritual and cultural heritage, and, therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self esteem, their native culture and they will become what we want them, a truly dominated nation".

Why I quoted this, Sir, every Speaker has mentioned about the subsidy, every Speaker has mentioned about theft, and, that is what was a different situation in 1835. This is very unfortunate situation that after independence, this has only grown. Sir, before coming to the main subject, I would say that my learned colleague hon. Bhatiaji has mentioned about Centre not supporting his State, Uttar Pradesh. I wish he could have been a little more tolerant than blaming the Centre for the faults of his own Government after losing the battle; because UPA is the only Government which has proved beyond doubt that they do not discriminate as to which Party's Government is there in a State.

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): आपका क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में आपकी सफलता का वर्णन कर दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): पाणि जी, डिस्टर्ब मत करिए। Please don't disturb. *(Interruptions)*

श्री संतोष बागड़ोदिया: सर, इनको मैं हिन्दी में समझा देता हूं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): अंग्रेजी में नहीं समझते, आप हिन्दी में बोल दीजिए।

श्री संतोष बागड़ोदिया: हमारी जो यूपीए की सरकार है, वह हिन्दुस्तान में किसी भी सरकार से भेदभाव नहीं करती। कोई भी व्यवस्था हो, चाहे डेवलपमेंट का काम हो, चाहे सब्सिडी का काम हो। राजस्थान में मेरा अपना अनुभव है कि हर साल हमारे यहां drought होता है। जितना पैसा यूपीए सरकार ने पिछले तीन वर्षों में राजस्थान को दिया है, उतना एनडीए ने भी कभी नहीं दिया। यह मैं केवल एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं। यह कहना कि पॉवर जेनरेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरह की बाधा यूपी के डेवलपमेंट के काम में डालेगी, मैं समझता हूं कि यह अपने आपको धोखा देने वाली बात है।

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, मैं तो समझ गया लेकिन ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): आप बैठिए। I am not allowing you. *(Interruptions)* I have not allowed you. *(Interruptions)*

श्री रुद्रनारायण पाणि: लेकिन जब माननीय मंत्री महोदय उत्तर दें, तब जरूर यह बताएं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री दो दिन पहले जब यहां आए थे, उनसे मिले थे, तब क्या-क्या निवेदन उन्होंने किया था? नवीन बाबू बहुत शांत व्यक्ति हैं, वे बहुत सिंपल व्यक्ति हैं। माननीय विद्युत मंत्री से वे क्यों मिले और किस कारण से उड़ीसा के बारे में मांग की ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): आप बैठिए। अब बैठ जाइए।

श्री रूद्रनारायण पाणि: कृपया पॉवर मिनिस्टर जब रिप्लाई करें, तब उसके बारे में वे जरूर बताएं।

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): वह अंदर की बात है, हाउस में नहीं कही जा सकती।

श्री संतोष बागड़ोदिया: पाणि जी, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप थोड़ा-बहुत टोक दीजिए। आप इतनी सारी बातें बोल देते हैं, मैं आपकी तरह विद्वान नहीं हूं इसलिए मैं उस बात को ही भूल जाता हूं कि मैं क्या बोलने वाला था। इसलिए मैं विनती करता हूं - इतनी लम्बी बात आप उड़ीसा के बारे में बोल गए, मैं भी चाहता हूं और मंत्री जी से कहूंगा कि जितना वे मांग रहे हैं, उससे ज़रा ज्यादा ही सपोर्ट दे दें।

श्री सुशील कुमार शिन्दे: मेरी उनसे जो बातें हुई हैं, सब बताउंगा तो इनको बुरा लगेगा।

श्री संतोष बागड़ोदिया: मंत्री जी, जब आपका नम्बर आए तो आप जरूर बता दीजिएगा।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया (झारखंड): सर, संतोष बागड़ोदिया जी मंत्री जी के कंधे को हिलाकर इतनी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं तो सदन में बोल काहे रहे हैं, कान में सब कुछ बोल दीजिए, जो बोलना है।

श्री संतोष बागड़ोदिया: ऐसा है कि मंत्री जी को तो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अहलुवालिया जी को हर बात में आपत्ति इसलिए हो रही है कि मंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। इसके अलावा वे हमारे पुराने दोस्त हैं।

Now, coming to the next point, Sir, somebody has just now mentioned about the NTPC also. The total requirement of the country and the total target fixed by the Government is about one lakh megawatts for five years, during the Eleventh Plan. That means, we have to add 20,000 megawatts per year. Obviously, we need equipment for that. Now, BHEL is one organisation which is already producing equipment to generate 8,000 megawatts of power. I am told that the Power Ministry is trying to advise their own department, NTPC, to put up a separate plant so that they can manufacture equipment for another 5,000 to 6,000 megawatts. I would like to request the hon. Minister, I am talking about BHEL, which is a Nav Ratna company and that is a unit which can produce 20,000 megawatts also. But, where are the buyers? You don't have plans. You don't have people who are willing to place orders for them. And, if you consider world

minimum requirement of this kind of unit, it is 20,000 megawatts. If you create and invest separate funds, for a smaller unit like 5000 or 6000 megawatts, it is not going to be viable, rather you will be competing with your own PSU, and may be both the PSUs become sick, because in the globalised economy, today, for all the mega projects or for other projects, there is an international bidding going on. People are coming from all over the world. And, against that competition, BHEL is competing successfully. I am sorry to say that there is something wrong in the communication between these two Ministries, the Ministry of Heavy Industries and the Ministry of Power. I think they are not meeting each other. I request you to please meet the hon. Minister of Industry and discuss with him. If you are not satisfied, you help BHEL itself so that they can produce up to 20,000 megawatts, provided you can arrange it. And, there is no use of wasting very hard-earned funds required for development of the country otherwise. NTPC has got enough. Their goal is to produce electricity. They have done very well in producing power so far. Let them continue with that. Please don't disturb them on that.

Sir, the National Common Minimum Programme states, "Households electrification will be completed in 5 years. The UPA will give special attention to augmenting and modernising rural infrastructure". Sir, electricity connections must be given to below poverty line families free of charge. Now, this is what we have been discussing—how to give this subsidy. I have absolutely nothing against subsidy being given to these people, or, giving free power even to the farmers. But, let us not mix up production of power, distribution of power and giving subsidy. Let there be a separate Budget for supplying free power to below poverty line families. Let there be a separate Budget from Ministry or Agriculture or any other Ministry, the Finance Minister has run away just now. I thought I would tell him to provide for this subsidy separately because by giving this subsidy through the present system, nobody knows how much subsidy is going. Nobody knows farmers are using how much power. As a result, this is free for all. As a result this subsidy is going to places where it is not required. Subsidy is going to small industries also. In some cases, it is going to medium industries also. In some cases, or, in most of the cases, subsidy is going to domestic consumers. It is just because we don't know how to handle this subsidy. Sir, as a result, the industries which are put up in villages, are suffering. Either they don't get power or they don't get quality power.

Sir, Gujarat is one State which I appreciate because they have got double grids in villages. One for the agriculture and one for the rest of the consumers. As Indiraji has mentinoed just now, the result is that at least the rest of the consumers, who are paying consumers, are getting power 24 hours and the production is not affected. Whatever amount of subsidy the State Government wants to give, the electricity is given to the farmers. Similarly, if all the States can have this kind of double grid in villages, production will not suffer. Another thing I am noticing is that these industries are moving from villages to towns, because they do not get power there. Forget about other infrastructure. In view of this, for no fault of theirs, they suffer. This aspect may please be looked into, hon. Minister, Sir.

Sir, another point is, creation of Rural Electricity Distribution Backbone (REDB) with at least one 33/11 kv (or 66/11 kv) sub-station in each block. You create that. That is a good idea. But, as I said, the grid should be separate. That may please be looked into.

Another point is, Decentralised Distributed Generation (DDG) systems where grid supply is not feasible or cost effective. Is it possible to set up village grids? Please look into it, hon. Mr. Minister, Sir.

Coming to the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana, one goal is to bridge the urban-rural gap and the second goal is to provide reliable and quality power to the rural areas. When we talk about rural areas, it says 81 per cent villages have been electrified and 19 per cent have not been electrified. It sounds very good: I do not know, Sir, but they say that there are three types of lies. One is a straight lie, like Bhatiaji mentioned just now. Another one is statistical lie. In my opinion, these are all statistical lies. Statistical lies are there not only in this sytem, but in all the systems. Sir, what is happening in this. I will give you an example, which I have given to hon. Minister previously also. Earlier, you know the system was, the villages were considered electrified if there was only one bulb. Now, I think, in 2004, the system was changed. Ten per cent consumers must get the power. I would like to know from the hon. Minister whether this 81 per cent is based on this 10 per cent and that only for one bulb.

श्री उदय प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश): संतोष बागड़ोदिया जी, मैं आपकी सूचना के लिए बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे-ऐसे गांव हैं, जिनमें घर के बाहर खम्बा तो लग गया है, लेकिन बिजली कभी नहीं आई है, उन्हें भी इलैक्ट्रिफाइड माना जाता है।

श्री संतोष बागड़ोदिया: मैं उस बात के ऊपर भी आ रहा हूं। आपने बहुत सही बात कही है। ...(व्यवधान)... Sir, after this new classification, I would like to know whether it is still 81 per cent. In Bihar, I think 39,000 villages have been de-electrified on the basis of old classification. And if you calculate it one the basis of new classification, probably all the villages in Bihar are de-electrified. By the number of villages, which are being electrified every year, I calculated it, Sir, it will take only 110 years to electrify all the villages of Bihar! In 110 years, we will be able to electrify all the villages of Bihar. I don't know are how we going to handle in five years. Bihar is also a part of the country. Similarly, my friend also has mentioned. नॉर्मली वे कविताओं में बोलते हैं, अभी पद्य में बोले हैं कि गांव में इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। लाइन खिच गई है, लेकिन पावर नहीं है। इसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा होती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थोड़ी कम है। क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स ने पूरा काम नहीं किया है, इसीलिए मंत्री जी ने यह नियम बनाया है कि पांच बरस में ...*(Interruptions)*... Sir, I will stop. Every point is not connected to each other. The moment you will ask me to stop, I will stop.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I have not said anything.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I thought you want me to stop.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, you can continue. You are making very good points. How can I ask you to stop?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, in Uttar Pradesh also, सारे देश में यह इलेक्ट्रिफिकेशन, जितना करना है, स्टेट गवर्नमेंट उतना काम पूरा नहीं कर रही थी, इसलिए यू॰पी॰ सरकार ने हमारी सोनिया गांधी जी और डा॰ मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया कि दिल्ली से इसकी फंडिंग की जाएगी और सारा रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। मैं मंत्री जी से केवल यही आशा करता हूं कि यह वास्तव में हो। बिहार में हो, यू॰पी॰, राजस्थान में भी हो। जिन प्रदेशों में नहीं हुआ है उनमें हो। अगर आप बोलेंगे कि पंजाब में कर दिया है, हिमाचल में कर दिया है, तो वहां पर तो ऑलरेडी हंड्रेड परसेंट है। कलकत्ता में भी कर दिया है। वेस्ट बंगाल में भी होना चाहिए।

Sir, the number of households electrified should be, at least, ten per cent which I have already mentioned. The National Electricity Policy envisages supply of quality power to rural areas for 24 hours. I wish this comes true, I will rather say, not in five years, not in six years, not in seven years, but, at least, in my life time. The way things are developing—we do

have big plans—but, unfortunately, the pace is very slow. Sir, if the hon. Minister does not become the President of the country—I would like him to—we will discuss this issue again after two years and we would like to see what kind of pace it has taken. If he becomes the President, I would request him to follow electrification maximum. With his push, probably, electrification in the country will happen during my lifetime. *(Interruptions)* Sir, only for statistical purpose, seven States have achieve more than 95 per cent village electrification, Rajasthan is also mentioned in the statistics given by some organisation, I think, the Government itself. But, I don't think, these are all correct statistics. That is why, I am saying that these are all statistical lies. Sir, five States have to do a lot because in these States, electrification is only 20 per cent....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You don't speak about Rajasthan. Only Bihar.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I have already said, it is not enough in Rajasthan. I am sure, our hon. Minister has come given me a smile and told me that sit down, I will look after Rajasthan. He has just now told me. Five States have less than 20 per cent household electrification. I would like to quote these States, Assam, Bihar and, of course, Mr. Pany's State, Orissa, Jharkhand and Uttar Pradesh. We have to think of new strategies. If the hon. Minister can give the State-wise details about the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana, it would be better. What are the financial and technical requirements for these franchisees? What is the revenue sharing arrangement between the franchisees and the REC? Is there any financial stake of the State Governments? How do you discipline these franchisees? Do you have any plan to discipline these franchisees also? Is it a State problem? Then you can simply say that it is a State problem. Either there is an overlapping of the mandate of the REC and the CPSUs or the REC has outsourced its mandate to the CPSUs. If there is overlapping, it means that one work is done by two people. With the kind of limited resources, it is better not to have overlapping. How many States have asked the CPSUs for help, as the States want to do it themselves? They want the CPSUs' help. But Bhatiaji would say that the Central Government is not giving help. I would like to know how many State Governments have asked for help and whether the Government is giving complete help to all the States.

Sir, according to section 14 of the Electricity Act, 2003, the States are required to notify rural areas.

Sir, if you want, I will finish. I will do that. But the Minister wants me to speak now. Whose order should I take? I don't know.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You have to take my order.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I will take your order.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now you try to conclude.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will you give me five more minutes? I will take exactly five minutes and I will stop. So far only 12 States have notified these areas. The States have been advised. I don't know whether Orissa is included in these States. If Orissa is not there, you request your State Government to notify them. आप जरा notify कर लें। मैं आपको फिर से बता देता हूं-According to section 14 of the Electricity Act, 2003, the States are required to notify the rural areas. Rural areas कौन से हैं, वह भी notify करना पड़ेगा। तो आप अपनी सरकार को बोलिए कि इनको बताएं, खाली 12 स्टेट्स ने notify किया है।

श्री रुद्रनारायण पाणि: पूरा उड़ीसा rural ही है। बहुत पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू 1952 में वहां गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं उड़ीसा के सबसे बड़े गांव को संबोधित कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Pany.

श्री संतोष बागड़ोदिया: वह भी notify करिए, इसमें कोई बात नहीं है, नियम तो follow करना पड़ेगा।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Pany, if you want, I will give you time. But don't disturb.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: The States have been advised to set up district committees and only 19 States have notified the same. अब ये सारा काम तो करिए अपनी स्टेट का। Deployment of franchisees is also to be done by the State Governments. A few State Governments feel that appointment of the franchisees will lead to cost escalation and need not be made compulsory. Demand for enhanced electricity is also to be met. An amount of

Rs. 1,100 crores was allocated for 2005-06 and the target was to electrify 10,000 villages. But only 6,300 villages had been electrified. If we don't meet the target, as I said earlier, it will take not 100 or 110 years but a very long time. For the year 2006-07, an amount of Rs. 3,000 crores have been allocated and the target of 40,000 villages has been fixed to electrify. We apprehend that considering the pace of physical and financial achievements during the previous year, the target for 2006-07 would be unachievable. Special attention should be given to the States which have a large number of unelectrified villages. The RGGVY will increase the demand for electricity considerably because this Scheme is not restricted to the households alone. Considering the present status of generation of electricity, we are concerned about meeting this demand by the Government. We are of the view that the electrification of villages should not just mean existence of infrastructure, but the people in the rural areas should really get electricity for their varied needs. It is not a question of only having a line. You have the line but there is no power. It has to be seen that there is complete matching between production of increased electricity and supply to rural areas. I must come to the last point; otherwise, I am sure the Minister, who is my childhood friend will become my old age enemy.

As on 4th May, 2007, 330 projects have been sanctioned by the REC, worth Rs. 12,008 crores against which Rs. 4,948 crores have been released. These 320 sanctioned projects cover 2,43,082 villages, out of which 74,472 are unelectrified and 1,68,619 are partly electrified villages. I want to mention these statistics so that the House can know that this is a very voluminous problem. It is good to say that electrify the rural areas, but, through you, Sir, I want to explain how difficult this work is. As on 4th May, 2007, electrification of 1,65,364 villages, including 63,333 unelectrified and 1,02,031 partly electrified have been achieved. It is a good achievement during the last one year or so. But can we maintain this pace?

My last point is, it is not the question of only supplying electricity, it is not the question of only quality power, it is the question of cost of power also. In case the cost of power is Rs. 7/- or Rs. 8/- or Rs. 9/- in the coming years, the supply of power will become useless. Only 10 per cent of the population in our country will be able to afford it. We have to complete in the world market. If we have to supply all kinds of good, to the consumers in the country, then power is the most important infrastructure which should

be available at a reasonable price. Would the hon. Minister ensure that during the next five years, power will definitely be available at less than Rs. 4/- or Rs. 5/- per unit and the increase will be just marginal. That can be possible if a lot of hydro power which has not been tapped in different parts of the country, is tapped more urgently than going in for any other kind of generation. With these words, I am thankful to the hon. Minister for giving me all assurances about Rajasthan.

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बिल एक संशोधन के रूप में आया है। 2003 में एक एक्ट बना और इस बिल के माध्यम से हम इसकी कुछ धाराओं में संशोधन करने जा रहे हैं।

महोदय, यूपीए गवर्नमेंट की ओर से एक राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया गया और सरकार इसके लिए वचनबद्ध हुई कि देश के सभी गांवों में, छोटे से छोटे गांवों में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इस समय बिजली आपूर्ति के मामले में शहरों और गांवों के बीच बड़ा असंतुलन है। अगर उस असंतुलन को दूर नहीं किया गया तो इस देश में दो भारत दिखाई देंगे-एक शहरी भारत और दूसरा ग्रामीण भारत। अभी माननीय अजय जी बोल रहे थे कि बरसों सिर्फ इस उम्मीद में पोल गाड़कर छोड़ दिया जाता है कि इस में तार लगेंगे और गांव में बिजली आएगी। विशेषकर जब चुनाव का समय आता है तो बहुत जल्दी में गांव में इस बात का प्रचार किया जाता है कि बिजली आ रही है और एक पोल भी गाड़ दिया जाता है। फिर दो-चार साल के बाद आंधी-तूफान में वह पोल नीचे गिर जाता है और गांव में बिजली नहीं आती। यह हमारे गांवों की स्थिति है। महोदय, राज्यों के बीच भी बड़ा असंतुलन है। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य हैं या दूसरे कई राज्य हैं, जहां नेशनल एवरेज से भी अच्छी स्थिति है।

महोदय, अभी बागड़ोदिया जी ने काफी आंकड़े देकर विस्तार से सदन को बताया कि अर्बन और रूरल क्षेत्रों की क्या स्थिति है। मेरे पास भी कुछ आंकड़े हैं जिन्हें मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं, हो सकता है इन में सुधार हो गया हो। महोदय, इलेक्ट्रीफाइड हाउस-होल्ड का भारत का शहरी आंकड़ा 87.60 परसेंट है और रूरल एरिया में इलेक्ट्रीफाइड हाउस-होल्ड 43.50 माना गया है। पंजाब की स्थिति यह है कि वहां अर्बन एरिया में 96.49 परसेंट है और रूरल एरिया में 89.46 परसेंट है, हरियाणा में अर्बन एरिया 92.94 परसेंट है और रूरल एरिया में 78.50 है जबकि बिहार में अर्बन एरिया में 59.3 है और रूरल एरिया में 5.1 है। महोदय, यह आंकड़े जो मेरे पास उपलब्ध हैं, उनके आधार पर बता रहा हूं। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर देश के विभिन्न राज्यों में इनता बड़ा असंतुलन होगा तो उस से भारत मजबूत नहीं होगा। यह माना जाता है कि जब तक शरीर के सभी अंग मजबूत नहीं होंगे तब तक शरीर मजबूत नहीं होगा। इसलिए अगर आप भारत

4.00 P.M.

को संपूर्ण रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं तो राज्यों के बीच में बिजली के मामले में जो असंतुलन है, उसे दूर करना पड़ेगा।

महोदय, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार में है और मुजफ्फरपुर में भी थर्मल पावर स्टेशन है। बरौनी की कैपेसिटी 320 मेगावाट की है और मुजफ्फरपुर में कांटी की कैपेसिटी 230 मेगावाट की है, लेकिन प्रोडक्शन कुछ नहीं है। महोदय, मेरे पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रोडक्शन 14 मेगावाट बरौनी में है, पता नहीं आजकल क्या स्थिति है और मुजफ्फरपुर में व कांटी में जीरो है। महोदय, बिहार में हाइड्रो कैपेसिटी 44.9 परसेंट है और प्रोडक्शन 8.6 प्रतिशत है। अब आज की स्थिति मुझे पता नहीं क्या है? बिहार को एन॰टी॰पी॰सी॰ से एक हजार से अधिक मेगावाट की सप्लाई होती है, जब बिहार के लोगों को बिजली मिलती है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बिजली नहीं मिलती है और बिजली न मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि बिजली से सिर्फ रोशनी ही नहीं मिलती बल्कि बिजली से खेती होती है और बिजली से छोटे-मोटे उद्योग भी चलते हैं। महोदय, आज ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का एक कारण यह भी है। महोदय, वहां आज भी 60 परसेंट खेती वर्षा के पानी पर निर्भर होती है और 40 परसेंट एश्योर्ड इरिगेशन पर निर्भर है जिस में लिफ्ट इरिगेशन भी है। वहां नदियों से पानी निकालकर या बोरिंग से पानी निकालकर खेतों तक पहुंचाया जाता है। यह इरिगेशन भी सेक्योर्ड इरिगेशन में शामिल है। अब अगर बिजली नहीं होगी तो वह कहां से पहुंचाएगा? अगर बिजली नहीं होगी तो पंप नहीं चलेगा, पंप नहीं चलेगा तो पानी नहीं आएगा और पानी नहीं आएगा तो खेती नहीं होगी। उसी कारण जो छोटे-छोटे उद्योग गांवों में चलते हैं, वे भी बिजली न रहने की वजह से बंद हैं। वहां से लोगों का पलायन हो रहा है। लोग गांवों से भाग कर शहरों में आ रहे हैं। इस प्रकार महोदय, बिजली की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की जो आर्थिक व्यवस्था है, वह व्यवस्था दिनों-दिन खराब होती चली जा रही है।

हमारे एक मित्र कह रहे थे—बिजली, पानी और मकान। मैं उसमें सड़क भी जोड़ता हूं। बिजली, पानी, मकान और सड़क। ये किसी देश के विकास के लिए या किसी राज्य अथवा क्षेत्र के विकास के लिए ऐसे कम्पोनेंट्स हैं कि अगर वहां ये कम्पोनेंट्स नहीं होंगे तो किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का और किसी देश का विकास नहीं हो सकता। महोदय, गांवों में कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास पावर है?—बिजली का दूसरा नाम पावर भी है गांवों में कहते हैं कि तुम्हारे पास पावर है? अगर पावर नहीं है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर पावर नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते।

महोदय, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का जहां तक सवाल उठता है, उसमें अब तक राज्यों की जवाबदेही होती थी। बिल में संयुक्त जवाबदेही की एक बहुत अच्छी बात कही गई है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों संयुक्त रूप से जवाबदेही लेंगे और दोनों संयुक्त रूप से मिल कर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे।

महोदय, सब्सिडी के बारे में भी चर्चा हुई है। अभी भी कृषि क्षेत्र की हालत यह है कि वह लाभप्रद नहीं रह गई है। कृषि के क्षेत्र में हम जितनी लागत लगाते हैं, उतनी भी आमदनी हमें नहीं होती है। बिजली के लिए किसानों को सब्सिडी की आवश्यकता है। वैसे बिजली बहुत मिलती नहीं है, जब समय पर बिजली की आवश्यकता होती है। शहरों में भी लोड शेडिंग होती है। बिजली नहीं मिलती है। मगर जो भी बिजली मिलती है और खेती की जो हालत है उस हालत को देखते हुए किसानों को सब्सिडी की बहुत आवश्यकता है।

महोदय, इस बिल में बिजली चोरी की भी बात की गई है। उसकी चोरी कौन करता है? क्या गांव के गरीब लोग? गांवों में जो गरीब लोग रहते हैं, वे बिजली चोरी से डरते हैं? बड़े अधिकारी की बात छोड़ दीजिए, एक चौकीदार भी अगर उसके दरवाजे पर चला जाए और कह दे कि तुम बिजली की चोरी कर रहे हो, तो वह कान पकड़ के पांच बार उठक-बैठक करेगा और कहेगा कि आगे से हम इस तरह का काम नहीं करेंगे। और वह कितनी चोरी करता है? कितने बल्ब्स जलाता होगा? एक, दो, तीन या चार। महोदय, बिजली की असली चोरी तो बड़े-बड़े उद्योगों, कारखानों में होती है। गांवों में रहने वाले ये ग्रामीण लोग बिजली की चोरी नहीं करते और अगर करते भी हैं तो वह इतनी कम होती है कि उसकी गिनती नहीं होती। बिजली की चोरी तो बड़े-बड़े कारखानों में होती है। बिजली की चोरी वैसे ही नहीं होती है। जब तक बिजली विभाग का कर्मचारी या अधिकारी उसका साथ नहीं दे, तब तक बिजली की चोरी नहीं हो सकती है। महोदय, मेरा यह कहना है कि चोरी को रोकने के लिए जो मोनिटरिंग की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। जब तक उस व्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे और जब तक बड़े-बड़े कारखानेदार, जो बिजली की चोरी करते हैं उन्हें नहीं रोकेंगे, उनको कठोर दंड नहीं देंगे, तब तक उसमें सुधार नहीं हो सकता है। हमारे एक माननीय् साथी कानून की बात कर रहे थे। मैं उतना कानून नहीं जानता, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि बिजली चोरी रोकने के लिए कठोर कानून होने चाहिए और उनका ठीक से पालन भी होना चाहिए। इसके लिए जिनको जवाबदेही दी जाती है, उनके द्वारा उसका पालन भी होना चाहिए।

महोदय, मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि बिहार जैसे जो पिछड़े राज्य हैं, जहां का औसत दूसरे राज्यों की तुलना में अभी भी बहुत कम है। अगर ऐसे राज्यों में, वह चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या दूसरे पिछड़े राज्य हैं, अगर उन राज्यों में बिजली की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तो जो मजबूत भारत, जो सम्पूर्ण भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं वह इन राज्यों के बिना अधूरा रहेगा इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण बिल को सदन के समक्ष लाया। आपका धन्यवाद, महोदय।

श्री सुरेन्द्र लाठ (उड़ीसा) : धन्यवाद, उपसभापति महोदय, जो आपने मुझे इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2007 पर अपनी बात कहने का मौका दिया।

महोदय, आज हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे देश में बिजली की आवश्यकता कितनी है और इसका महत्व कितना है। स्वाधीनता के बाद जिन लोगों ने भी इस देश की योजना बनाई,

उनका आकलन शायद सही ढंग से नहीं हो सका, जिसके कारण आज यह स्थिति हो गई है कि हम बिजली देश के सभी गांवों, गांव की बात तो क्या कहें, शहर तक भी पूरी बिजली हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसे सब लोगों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि बिजली की स्थिति क्या है? बहुत सारे क्षेत्रों में तो आज दिन में दस-दस घंटे तक बिजली उपलब्ध नहीं रहती है, कई प्रदेशों में तो दिन में केवल तीन या चार घंटे ही बिजली आती है और अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात कहें, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां कभी दो-तीन दिन में एकाध बार ही बिजली आती है। यह ऐसी अवस्था क्यों हुई? कहां गलती रही है? निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने भी योजनाएं बनाई हैं, उनका आंकलन कहीं न कहीं गलत रहा होगा, हमारी योजनाओं को वे ठीक ढंग से मालूम नहीं कर सके। इसके कारण से आज इस प्रकार की अवस्था हम देश रहे हैं और इसी के कारण से देश के विकास में बाधाएं आ रही हैं, हमारे औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है।

महोदय, बिजली एक ऐसा विषय है, जिसके बिना इस देश के विकास की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम सब जानते हैं आज देश के अधिकांश बिजली बोर्ड भारी नुकसान में चल रहे हैं और दिवालियापन की कगार पर खड़े हैं। इन सब बातों को ध्यान मे लाकर बिजली या इलेक्ट्रिसिटी में सुधार लाने के उद्देश्य से NDA सरकार के समय में वर्ष 2003 में इलेक्ट्रिसिटी बिल इस सदन में और उस सदन में पास किया गया था, किन्तु कोई भी बिल अपने आप में पूरा नहीं होता, उसमें समय-समय पर संशोधन की गुंजाइश भी रहती है। शायद इस सरकार ने इसी उद्देश्य से इस बिल के माध्यम से कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इसमें जो मुख्य रूप से संशोधन लाए गए हैं, उस बारे में सेक्शन 6 में कहा गया है कि ग्रामीण विद्युत की जो जिम्मेवारी है, वह इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 में राज्य सरकार तक सीमित थी, उसको बढ़ाकर केंद्र सरकार को जोड़ा गया है। यह जो ग्रामीण विद्युतीकरण की सारी जिम्मेवारी है, वह केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल कर निभाएंगे, इसी उद्देश्य से इसमें संशोधन किए गए हैं।

महोदय, अभी कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि कितने ही गांवों में वहां के लोगों को अभी तक हम बिजली नहीं दे पाए हैं और यहां सवा लाख गांवों की बात भी कही जा रही थी। तो देश के सवा लाख गांवों में अभी तक हम बिजली नहीं पहुंचा पाए हैं। इतना ही नहीं, देश के 55 से 60 परसेंट हाऊस-होल्डस में आज तक हम बिली नहीं दे पाए हैं, जो without electricity हैं। कई प्रदेशों में तो यह प्रतिशत 80 प्रतिशत तक है। जैसा माननीय भंडारी जी अभी कह रहे थे, बिहार की स्थिति क्या है, झारखंड की स्थिति क्या है? वह हम सब जानते हैं। यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जब हम इस इक्कीसवीं सदी में अपने देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में निर्माण करने की बात कर रहे हैं, वहीं अगर हम देश में 55 से 60 प्रतिशत घरों में बिजली नहीं दे पाएं, तो किस प्रकार के विकास की कल्पना हम कर सकते हैं?

महोदय, आज ग्रामीण क्षेत्रों में हम बिजली देने की जब बात करते हैं, तब हम सब जानते हैं कि वहां हम किस प्रकार की बिजली देते हैं। कई गांवों में खंभे खड़े कर दिए जाते हैं, तार जोड़ दिए जाते हैं और सरकारी आंकड़ों में कह दिया जाता है कि अमुक गांव में बिजली पहुंच गई है। सरकार ने, निश्चित रूप से, डेफिनेशन में कुछ संशोधन किए हैं, उसमें यह कहा गया है कि 10 प्रतिशत घरों में बिजली पहुंचने पर ही उस गांव को विद्युत ग्राम घोषित किया जा सकता है, यह एक अच्छा कदम है। लेकिन, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि केवल 10 प्रतिशत ही क्यों, जब तक हम 50 प्रतिशत घरों में बिजली नहीं पहुंचाते हैं और गांवों के सार्वजनिक स्थानों तक हम बिजली नहीं पहुंचाते हैं, तब तक उस गांव को हम इलेक्ट्रिफाइड विलेज के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। महोदय, अगर हम इस क्राइटेरिया को लेंगे, तो जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, वे आंकड़े बहुत आगे तक जाएंगे, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस संशोधन के माध्यम से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को ग्रामीण विकास में साझीदार बनकर बिजली पहुंचाने की जो बात कही गई है, वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है।

महोदय, दूसरा अमेंडमेंट, जो कॉस्ट सब्सिडी के बारे में है, उसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में ऐलिमिनेशन आफ इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के बारे में कहा गया था और शायद इसके पीछे उद्देश्य यह रहा होगा कि कई बार राजनीतिक कारणों से हम मुफ्त बिजली देने की बात कहते हैं या बिजली बिलों को माफ कर देने की बात भी कहते हैं, जिससे प्रदेशों का, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का बोझ अधिक मात्रा में बढ़ता है। किन्तु, इसके साथ-साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि आखिर इस देश के लोगों को हम बिजली क्यों नहीं दे पा रहे हैं? गांवों में 60, 70 या 80 प्रतिशत घरों में बिजली क्यों नहीं पहुंच पा रही है? महोदय, आज गांवों का 80 प्रतिशत बाशिंदा बिजली के तारों को अपने घर तक पहुंचाने में, बिजली का बिल अदा करने में सक्षम नहीं है और जिस प्रकार इन पांच बरसों में बिजली की कीमतों में वृद्धि हुई है, उससे इस समस्या में अधिक विस्तार हुआ है।

महोदय, इसके अलावा कई छोटे-छोटे कुटीर उद्योग हैं, जिन्हें चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, किन्तु जिस प्रकार से बिजली की दरें बढ़ती जा रही हैं, ये छोटे-छोटे उद्योग उन दरों को देने में असमर्थ होते जा रहे हैं और ये उद्योग बंद होते जा रहे हैं। महोदय, हम जानते हैं कि आज देश का कृषि के बाद सबसे बड़ा क्षेत्र, जिसमें सबसे अधिक रोजगार का सृजन होता है, वह छोटे-छोटे उद्योग या कुटीर उद्योग का क्षेत्र है। इन उद्योगों को सरकार की सहायता की आवश्यकता रहती है और बिजली की दरें जिस प्रकार से बढ़ रही हैं, निश्चित रूप से सरकार को इनके बारे में गंभीरता से विचार करना होगा, ताकि ये उद्योग बंद न हों, ये उद्योग अधिक मात्रा में चल सकें, इनसे अधिक रोजगार का सृजन हो सके। इसीलिए, इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में जो सब्सिडी देने की बात है, इसे चालू रखना होगा, धीरे-धीरे इसे कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए हमें विचार करना जरूरी है। किन्तु हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हम जो सब्सिडी दे रहे हैं, उस सब्सिडी का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके।

महोदय, कई बार इस सब्सिडी का लाभ जिन्हें मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिलता है, इसके माध्यम से कई उद्योगपति लाभ लेते हैं। सरकार इस बारे में नियम बनाए और नियमों के माध्यम से इस बात की चिन्ता करे कि इन सब्सिडीज का दुरुपयोग न हो।

महोदय, तीसरा जो संशोधन है, वह बिजली की चोरी के बारे में है। हम सब जानते हैं कि देश में बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी होती है और सालों से यह चोरी हो रही है। यह एक प्रकार की chronic disease हो गई है और कई जगह पर तो इस प्रकार की भावना भी देखने में आई है कि बिजली चोरी करना हमारा मौलिक अधिकार है। अभी आदरणीय भंडारी जी कह रहे थे कि बिजली की चोरी छोटे-छोटे कंज्यूमर नहीं करते है। यह बात भी सही है। आप देखेंगे कि 80% बिजली की चोरी बड़े-बड़े उद्योगों के माध्यम से होती है और विभिन्न उपायों से ये उद्योग इससे बचते रहते हैं, किन्तु कभी उनकी लाइन नहीं काटी जाती है। वहीं दूसरी ओर, कहीं एक छोटे कंज्यूमर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटि बिल देने में भूल हो गई तो उसका कनेक्शन पहले काट दिया जाता है।

महोदय, चाहे बिजली की चोरी का मामला हो, मीटर टेम्परिंग हो या कोई और कारण हो, इस संशोधन के माध्यम से उसे cognisable offence बनाया गया है। पुलिस को उसमें इन्वेस्टिगेशन करने या उसके अगेन्स्ट FIR फाइल करने को अधिकार दिया गया है और इस माध्यम से बिजली की चोरी को रोकने का प्रयास किया गया है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इससे बिजली की चोरी में निश्चित ही कमी होगी और अगर बिजली की चोरी में एक बार कमी हो गई तो निश्चत रूप से quality of electricity, जिसकी आज कमी है, उसमें भी सुधार आएगा। कहीं न कहीं इसका प्रभाव बिजली के रेट्स पर भी पड़ सकता है, उसमें कमी आ सकती है।

महोदय, इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी मात्रा में Transmission Loss भी हो रहा है, उसे भी कम करने की आवश्यकता है। आज ये जो संशोधन लाए गए है, निश्चित रूप से ये बिजली के क्षेत्र में सुधार लाएंगे।

महोदय, मैं एक-दो बातें और कहना चाहता हूं। आज बिजली के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में निजी क्षेत्र आ रहे हैं। चाहे डिस्ट्रिब्यूशन हो, ट्रांसमिशन हो या प्रोडक्शन हो, सबका निजीकरण हो रहा है।

महोदय, मैं उड़ीसा से आता हूं और उड़ीसा पहला ऐसा प्रदेश है, जिसने विद्युत सुधारों को ग्रहण करके अपने यहां पर लागू किया है। डिस्ट्रिब्यूशन, ट्रांसमिशन, प्रोडक्शन इत्यादि की अलग-अलग कंपनियां बनाई हैं, अलग-अलग निजी कंपनियों को इसका काम सौंपा गया है। किन्तु अगर अनुभव के आधार पर देखा जाए तो आप जान सकते हैं कि इससे Quality of Electricity में कोई सुधार नहीं हुआ है, स्थिति बद् से बद्तर हुई है साथ ही ट्रांसमिशन लास, जिसे हम कम करने

की बात करते थे, उसमें भी कोई विशेष कमी नहीं आई है। उत्पादन में निश्चित रूप से कुछ सुधार हुआ है। किन्तु इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वह नुकसान उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों का हुआ है, निजी क्षेत्रों में यह व्यवस्था जाने के बाद उड़ीसा में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजलीकरण बंद सा हो गया था। इन निजी कम्पनियों की कोई रुचि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने की नहीं है। इसके कारण उड़ीसा का विद्युतीकरण का जो कार्यक्रम था वह बहुत पीछे रह गया। महोदय, मैं निजी क्षेत्र के विरोध में नहीं हूं किन्तु निजी क्षेत्र करने के साथ-साथ उन पर अंकुश करने की आवश्यकता है। हमारे सामाजिक दायित्व कैसे पूरे हो सकते हैं उसको भी देखने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे प्रदेशों में डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क आपने निजी क्षेत्रों को दिया है। हमें आवश्यकता है कि निजी क्षेत्रों को देने के बाद इनमें कितना सुधार हुआ है इसकी भी समीक्षा करने की आवश्यकता है। महोदय, अभी निजी क्षेत्रों में उत्पादन बड़ी मात्रा में आ रहा है, बहुत सारे हमारे लोग ओपन एक्सेस की बात कर रहे हैं और इस क्षेत्र में कैसे अधिक कम्पटीशन आ पाए, जिससे लोगों को, उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सके इसकी भी बात की जा रही है। किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि जब तक डिमांड और सप्लाई का गैप आप कम नहीं कर पाएंगे तब तक यह ओपन एक्सेस सिस्टम सफल नहीं हो सकता है। जब तक उत्पादन को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक हम इस क्षेत्र में कम्पटीशन की बात नहीं कर सकते हैं। इस बारे में बहुत से आंकड़े हमारे मित्रों ने दिए हैं मैं आंकड़ों पर अधिक जाना नहीं चाहता हूं, सारे आंकड़े माननीय मंत्री जी के पास हैं, वे उसे देखेंगे।

मैं एक और बात कह कर अपनी बात समाप्त करुंगा। महोदय, देश के बहुत सारे पिछड़े प्रदेश हैं जिनमें इलैक्ट्रिसिटी - बिजली पहुंच नहीं पाई है, विशेषकर उड़ीसा जैसा प्रदेश जहां आज भी 10 हजार से अधिक गांव तक बिजली नहीं पहुंची है और जो नया क्राइटेरिया फिक्स हुआ है अगर उसको देखेंगे तो बिजली बीस हजार गांव तक पहुंच जाएगी। वैसे ही बिहार की स्थिति, झारखंड की स्थिति, छत्तीसगढ़ की स्थिति, उत्तर प्रदेश की स्थिति इन सब प्रदेशों की स्थिति बहुत खराब है। आश्चर्य की बात तो यह है कि अगर आप देखेंगे तो झारखंड में, उड़ीसा में जहां कि सबसे अधिक कोयला है, सबसे अधिक बिजली का उत्पादन भी हो रहा है उसके बावजूद इलैक्ट्रिसिटी वहां उपलब्ध नहीं हो रही है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इन पिछड़े प्रदेशों में प्राथमिकता के आधार पर बिजली पहुंचे। आपने 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक गांव को बिजली पहुंचाने की बात कही है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव तक कैसे बिजली पहुंचे, इसके बारे में योजना की है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को आरम्भ हुए दो साल हो गए हैं लेकिन इसका जो परफार्मेंस है वह कहीं भी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर नहीं दिख रहा है। इसमें गति आने की आवश्यकता है। हम अधिक तीव्रता से इसमें कैसे काम कर सकें इसकी आवश्यकता है। केवल योजना बनाने से सफल नहीं होगी, योजना को नीचे स्तर तक कार्यान्वयन कैसे होगा इसके बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता है। महोदय, मैं अधिक समय नहीं ले रहा

हूं। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, फिर से मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा, हमारे पाणि जी कह रहे थे कि आपसे मिलने के लिए हमारे राज्य के मुख्य मंत्री जी आए थे, उन्होंने आपसे बहुत सारी बातें की हैं। आप हमारे प्रदेश के बारे में थोड़ा अधिक ध्यान दें, यह मेरा अनुरोध है। हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है, जहां पर 47-48 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, जहां पर 55 से 60 प्रतिशत घरों में बिजली नहीं पहुंच पाई है, मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इस ओर निश्चित रूप से ध्यान देंगे। मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI SYEED AZEEZ PASHA (Andhra Pradesh): Thank you Mr. Vice-Chairman, Sir, for having given me this opportunity. Needless to say, energy is the main key factor for any country's advancement. But what we have been seeing for the past six decades is that the condition is far from satisfaction. Though we have been putting several targets, yet we have not been able to achieve the targets. As a result, we see that in the rural areas we are not in a position to get electricity supply even for 4-6 hours. If we take the examples of Bihar and Uttar Pradesh the situation is really precarious. So, to overcome all these things, it is very much necessary to mobilise resources. As the hon. Finance Minister has so many times said that there was no paucity of funds, we can provide a good amount for this purpose. For the coming period, it seems that there is a necessity of investing a minimum of Rs. 7 lakh crores. It is only to reach a satisfactory level, not to speak of optimum level. However, we have to that have that resolution. With regard to rural electrification, under the Rajiv Gandhi Gramin Vidyut Yojana, the target was to electrify 68,763 villages. But we have been able to cover only 36,000 villages. So, there ae still 32,763 villages which are yet to be covered by, I think, 2007-08. Even after sixty years of Independence, there is no electricity in several rural areas. This is not a good situation for any country's progress. The fund allocation in the year 2007-08 was Rs. 3,983 crores, though the requirement was Rs. 8,500 crores.

Sir, we have an immense potentiality in the hydro-electricity. For example, in Arunachal Pradesh, nearly 50,323 MW can be produced through hydroelectric projects. But we are not fully concentrating on this. We have not been able to harness the potentiality of the hydroelectricity because of certain problems, like, the clearance from environment and forest angle, the rehabilitation and settlement of the affected people, delay on the part of State Governments in land acquisition, and so on and so forth. But, a determined effort from the Government should overcome all these hurdles

and problems. In this connection, one undesirable thing to my understanding is that it seems that we are going to give blanket approval below 100 MW to all the private bidders. I think, it is not proper and desirable. When the Government says that it has no financial crunch why should it hand over the entire project to the private people?

Then, I come to my State of Andhra Pradesh. There are two gas-based stations which were approved by the Ministry. But we are seeing that they are not in a position to supply gas. Even though the State Government is ready, while preparing the infrastructure, now we are told that you go and have it through naphta. You know naphta means it will be a very costly affair. We are having a lot of gas in Krishna and Godavari Basin, then, why don't you divert that gas to these projects? What we are seeing is that they are depriving one State and are providing to other States, which is not proper. This is what I feel.

Another problem is regarding one thermal power station at Ispat near Bilaspur where the people or the peasants whose lands have been taken over are agitating for the past 8-10 months. They are asking for proper compensation for the land which was taken over by the thermal station. And, they are asking for compensation, that is, give employment to one person from one family, who has been uprooted due to this project. I have already submitted thousands of signatures to the hon. Minister of Power, Shri Shinde. But, I am sorry to say that still no proper action has taken in this regard.

Sir, pilferage and theft, which we are seeing today, is a very chronic disease. As my learned friend just now said, compared to a common consumers, who is using 10-20 units, we are seeing that industrial houses are indulging in pilferage causing losses in crores of rupees to the State Exchequer. So, it is good that we are now proposing certain amendments in regard to punishment for the offences committed. But, here I want to just give a word of caution. In the name of punishing the persons who are indulging in pilferage — even though we are not against taking instant action against pilferage — we must take some sort of caution. In the name of checking pilferage, the toll should not fall on the poor consumer. I have seen so many cases and I come across so many cases where for a small mistake a huge bill of thousands of rupees is being levied upon them. Otherwise, there is a threat of sending them to jail or putting them

behind bars. That is why, while taking concrete steps, I only want to insist upon the Ministry that we should not take harsh or arbitrary measures against the poor consumers who are utilising only a small part of it.

So, these are some of the points which I wanted to say. Finally, I want to say that electricity should be supplied to each and every consumer, particularly, the common man at affordable prices. So, hydroelectricity will be the main source. If we tap hydroelectric energy, definitely, we can supply electricity at affordable price of Rs. 10-12 per unit. I think that should be our target. Thank you very much.

SHRI B.J. PANDA (Orissa): Thank you, Mr. Vice-Chairman, sir, for giving me this opportunity. This Electricity (Amendment) Bill, 2007 contains some very good features, but it also contains, at least, one seriously regressive feature, which I will point out in due course. Sir, to understand this, we must go back seven years and understand how the Bill, which we are today amending, came about. Sir, in the year 2000 this Bill was first proposed because we had almost 90 years of antiquated laws. We had the Electricity Act, 1910. We had the Electricity Act of 1948 and we had a myriad number of small incremental changes that had been made in the law in the previous ten years from the year 2000. Therefore, this draft Bill in 2000 was referred to the Energy Committee. I was privileged to be a Member of that Committee. Sir, it is important to note that hundreds of hearings took place so that every stakeholder's viewpoint could be incorporated into this Bill, which then became the Act. Sir, it took a long time. The draft Electricity Bill, 2000, became the draft Electricity Bill 2001. Subsequently, it got further extended and became the draft Electricity Bill, 2003 and then it was passed as an Act in 2003. Sir, viewpoints of every possible stakeholder, from trade unions to industries, to consumers, to investors, to NGOs, to activists, were included and that is how it should be done in a democracy, because we were changing nearly a century-old law and we wanted to make our law up-to-date for the 21st Century. Sir, what is more important than the fact that so many hearings took place was that it was a bilateral effort. Sir, important Members from both sides, from the Treasury Benches and the then Opposition Benches played a very important role in developing many of these clauses. I have personally worked with the colleagues of the hon. Minister today in the Cabinet, who were then in the Opposition, in shaping some of these clauses so that they were acceptable to everybody. So, Sir, bringing about changes in this

should not be taken lightly. I am not sure how much effort has gone into it. Another aspect of evolution of this Act was that the draft Bill itself went through seven or eight changes. It was listed on the website of the Ministry and many hundreds and thousands of letters and e-mails were received from all over the country, apart from all the hearings that the Committee had. Sir, thus, when the Committee endorsed this Bill which became the Act in 2003, it had every possible viewpoint. It was a bilateral effort from both sides, the Government and the Opposition Benches, and it reflected the best possible judgement of all the minds taken together. I am concerned, Sir, that, maybe enough, a similar effort has not been made this time in bringing about some of these amendments. Nevertheless, Sir, I would like to compliment the hon. Minister that many good changes have been brought about. What has been brought about, which is good, is what was discussed at the time of passage of this Bill in 2003, where due to various compromises of differences of opinions, some aspects were left behind. The hon. Minister's predecessor had pointed out that these would be subsequently taken up; I am glad to notice that some of them have been subsequently taken up. Sir, we must give credit where credit is due. One of my hon. colleagues has pointed out the role that was played by my State when, under the leadership of late Shri Biju Patnaik, the very first Electricity reforms were brought about in this country in the early 90's. There were other States also which played some pioneering role. We may have political differences with some of them, but I will not hesitate to give credit to the State of West Bengal where one of the very important changes was brought about. I remember, as a Member of the Committee, when we toured all over the country, and we took hearings in West Bengal, we were very pleasantly surprised to see that it was the first State which had pioneered cognisance of theft of electricity as an offence under the Criminal Code. This was a very vital turning point and although many of us wanted to include this in the Act in the first time, it had to be left out for various considerations. This was one of the issues where the then Minister had assured that this would be taken up in due course. I am very glad that it has been taken up. Sir, there have been some false understandings based on which theft of electricity was not made a cognisable offence in the past. As some of the hon. Members have pointed out today, it has been vastly misunderstood that theft is primarily done by the poor people. So, somehow, with a feeling of sympathy and empathy for the large number of poor people in our country, many of our hon. colleagues in

the past have touched this or not touched this – a very ginger subject – because it might be touching the poor people but that is not the case. Apart from what you have heard from the hon. colleagues today in the House, evidence is coming out. For example, in Delhi, many NGOs have conducted some studies and clear evidence is coming out that there are more instances of theft among the affluent colonies than there are instances of theft among the poor people. So, Sir, we should not at all be afraid to touch the issue of theft and treat it as it should be treated, which is theft. I am very glad that we are now making it a national law, as it used to be in the State of Bengal, that anywhere in India, electricity theft will be treated as a cognizable offence and that the Police will be authorised to investigate it. This is the way that the country can move forward, Sir, and I fully endorse this.

Sir, I have to say with regret that there is one seriously regressive bit of amendment which I would urge the hon. Minister to reconsider. Sir, this is a backtracking of the process of modernisation of our Electricity Act and laws, and this has to do with cross subsidy. Sir, I would like to take a little time to just explain what it is that I am pointing out. Sir, once again, this is a subject which has been much misunderstood. Sir, I am not against subsidy. In fact, I am for subsidy. The vast numbers of poor people in our country deserve a helping hand to get access to cheap and affordable electricity. These are the honest poor people who do not steal; these are farmers; these are the lower middle class people; these are other kinds of poor people who deserve this helping hand and we should give them subsidy as we give subsidy for those sections of our population whether it is in food, whether it is for fuel or whether it is for other areas. We give subsidies. Energy is a vital area. Sir, if we do not provide that subsidy, it has many other catastrophic problems. For example, vast numbers of our poor citizens burn wood; they cut trees illegally for their energy requirements. This has a disastrous effect on the whole, globe as a whole. So, Sir, I am not at all against subsidy. I am for subsidy. But the misunderstanding that persists is that cross subsidy is the same thing as subsidy. It is not. Sir, cross subsidy simply is that you charge higher than justifiable tariff to some sector such as industry in order to subsidise the poor people. Sir, the problem with this argument is, there is an old saying which sums this up. It is called 'robbing Peter to pay Paul'. Sir, we need to pay Paul, but we do not need to rob Peter for it. Sir, I tell you why we don't

need to do it. Many times in this august House, we have discussed that because of globalisation, because of the way the world is going and the way our economy is going, our industries are not able to compete with the industries of other countries. Specifically it has been discussed that our industries are not able to compete against industries in China. We must provide a level-playing field. It is not a fact that we should treat our industries as some kind of *'parayas'*, which should be squeezed unnaturally, just so that we should provide subsidy to those deserving citizens of ours. Once again, I repeat, Sir, we must subsidise our deserving citizens for cheap and affordable energy, but not at the cost of any other section. Sir, just like when we provide food subsidy to our poor people, we don't force our better-off people to pay more for food. We pay it from our tax revenues. And, today, Sir, our tax revenues are very buoyant. Today, we can afford to do the right thing which is to subsidise those deserving citizens from our tax revenues, not by penalising another sector of society which is also contributing to our development. Particularly, since this would handicap us, it will handicap our country's economy, it will handicap our country's ability to generate employment, and what happens when we put cross subsidy burden on another section of society is that investments in those sectors, jobs in those sectors will get exported to countries like China. That is not the right thing. We must subsidise, but we must do it correctly and, that is why, in the Act in 2003, after hundreds of hours of discussions of every persons' input, it was mandated in the Act that cross subsidy will be gradually reduced and eliminated. Sir, this is the regressive step in item 10 in this Bill today which is Section 61(g). The hon. Minister proposes the word 'elimination' to be removed. That means, the objective of removing cross subsidy gradually over a period of time is no longer there. It is a very subtle change, Sir, but it has and it will have a very long-term impact. I have just pointed out the principle of the thing. Let me point out some other defects with not eliminating cross subsidy. Sir, the reduction of cross-subsidy is still there, elimination is removed, but what it says is, the reduction of cross-subsidy will be decided by an appropriate commission's directives. What does that mean, Sir? It means subjectivity; it means discretionary powers. That is something that we have tried to remove as we modernise our laws in this sector; we have tried to make it rule-based. We should put rules in place and not subjectivity or discretionary powers.

Sir, this, Act which was passed in 2003, took three years for many reasons. One reason is that there are a large number of very powerful lobbies that were lobbing everybody present; they were lobbing us Members of Parliament, they were lobbing the media, they were lobbing the statutory bodies, so that the wordings could be framed to suit them. And I am very happy to note that in almost all the cases those lobbies were defeated. Because of the democractic process, because of the widespread consultations, those lobbies could not get their voices into the Act. When you have subjectivity in the hands of administrators, they are susceptible to lobbying. We should not have subjectivity - the subjectivity of deciding how much will be the reduction in cross-subsidy. Whether you would reduce by one per cent or five per cent this year will be subject to lobbing by various sources. We should not have that. I strongly urge upon the hon. Minister that we must have it rule-based and you must reinstate the principle of the position, which was widely discussed throughout the country, that not only should it be gradually reduced but it should be eliminated too. I would reiterate for the hon. Minister's understanding so that there is no doubt, that I do want subsidies to continue for our deserving poor citizens, but not through this means.

Sir, this issue has been talked about at length by many hon. colleagues and I shall not take up the House's time. There are other issues which have been taken up. I would just like to conclude by raising one issue which is not really a part of the Bill but part of the rules and some of the schemes. In the Rajiv Gandhi Rural Electrification Programme, which has been talked about quite a lot, I find that the benefits that we were expecting in our State are not really translating because of some of the norms that have been put in place. One norm that has been put in place, Sir, is that only villages with a minimum population of 300, and above, will be catered to and provided funds for this rural electrification. That may work in certain areas of the country and certain States. Ours is a widely disparate kind of a State. We have a large coastal region, we have a large interior and highly forested region, we have a hilly region, we have 25 per cent tribals, one of the largest tribal populations in the country, and we have many small hamlets which do not meet this requirement of a minimum population of 300. I would urge upon the hon. Minister to reconsider that because what will happen is, it may sound reasonable that because of economic considerations you have to have some cut off, say 300, but in

reality, it will tilt the balance and the development funds may go to certain areas and not to certain other areas where we have a more scattered population. Perhaps the hon. Minister would reconsider this and instead of having a minimum of 300 people, it could perhaps be made 150.

Sir, with that, I would like to thank you to giving me this opportunity and once again, urge upon the hon. Minister to take these points into consideration.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Thank you, Mr. Panda, You made good points. Mr. K.P.K. Kumaran.

SHRI K.P.K. KUMARAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman Sir, it is a laudable aim of the UPA Government to provide access to electricity to all areas including remote villages. They have also backed up this aim with more than Rs. 16,000 crore which is to be appreciated.

Sir, I have just one suggestion which is regarding the area of power generation. It is seen that when there is xcess power generation and there is more power than the grid can handle, there are instances where the windmills and the hydel power plants are shut down but the thermal power plants keep operating. Right now, global warming is a big issue and the detrimental effect of greenhouse gases and so on has been documented. It is also a known fact that thermal power plants cause more damage to the environment than clean sources of power such as windmills and hydel power. So, our policy should be amended in such a way that whenever there is excess power generation, we make full utilisation of clean sources of power such as windmills and hydel power and if at all any power plant has to be shut down, it should be the plant that causes more damage to the environment such as the thermal power plant.

Sir, I would place this suggestion for the consideration of the hon. Minister. I support the Bill and thank you for this opportunity.

श्री विजय कुमार रूपाणी (गुजरात): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन देर से आने पर भी दुरुस्त आया है। हमारे यहां गुजरात में जब नरेन्द्र भाई की नयी सरकार बनी, तब गांवों के लोग उनसे मिलने के लिए आए थे और वे बता रहे थे कि आज़ादी के 60 साल के बाद अब यह करो, वह करो, यह हम नहीं कहते हैं, लेकिन इतना जरूर करो कि शाम के वक्त जब हम खाना खाने के लिए बैठे, तब हमारे घर पर बिजली रहनी चाहिए, आज तक जब हम शाम को खाना खाने के लिए बैठते हैं, तब बिजली नहीं

होती है और रात को जब बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, तो बिजली नहीं होती है, इसलिए 60 साल की आज़ादी के बाद यह जो दृश्य है, इसको आप बदलिए।

महोदय, इस देश में बिजली की स्थिति पर आज यहां चर्चा हुई कि आज भी देश में 40 परसेंट गांवों में अभी भी 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है और एक लाख गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। इसका मतलब यह है कि अभी तक जो कुछ हुआ है, वह कम हुआ है और हम मानते हैं कि देश के विकास के लिए जिन 5 शक्तियों की आवश्यकता है, हम उनको पंचामृत बोलते हैं-उनमें पहली ऊर्जा शक्ति है, दूसरी जल शक्ति है, तीसरी विज्ञान शक्ति है, चौथी रक्षा शक्ति है और पांचवीं जन शक्ति है। इन पांच शक्तियों का जब जागरण होगा, तभी देश की उन्नति होगी। तो आज ऊर्जा शक्ति की बहुत आवश्यकता है और हमारे देश में एक लाख मैगावाट का power deficit है और इसके कारण देश की यह स्थिति है। आज जो चर्चा हुई, उसमें tariff की बात हुई, अभी पंडा जी ने बताया कि हम बड़े लोगों से ज्यादा पैसे लेते हैं और subsidy देते हैं, तो वह क्यों है? यह इसलिए है कि जो राज्य के बिजली बोर्ड हैं, वे बोर्ड आज बहुत से राज्यों में deficit की हालत में है। हमारे गुजरात में भी नरेन्द्र भाई की सरकार से पहले 2,200 करोड़ रुपए का deficit हर साल होता था और उसको हमने बदला। आज हम मुनाफे में आ गए हैं और हमारा मुनाफा 200 करोड़ रुपए का हो गया है, 2,200 करोड़ रुपए के नुकसान से ऊपर उठकर हम 200 करोड़ रुपए मुनाफे में आ गए हैं। यह क्यों हुआ, कैसे हुआ? पूरे देश में यह होना चाहिए।

महोदय, आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि गुजरात ही एकमात्र ऐसा राज्य है कि ज्योर्तिग्राम योजना के अंतर्गत गुजरात के सभी गांवों में 24 घंटे तक without interruption हमने बिजली दी है। वहां 24 घंटे बिजली मिलती है, 3 फेज़ बिजली मिलती है और without interruption यह बिजली हम दे रहे हैं। हमने इस ज्योर्तिग्राम योजना के तहत 18,000 गांवों को ज्योर्तिग्राम बनाने के लिए एक लाख किलोमीटर नयी wire डाली है , इसका मतलब यह है कि पूरे राज्य में हम wire को फैलाएंगे, इतनी wiring हमने की है। हमने 206 नए सब-स्टेशन बनाए। आज कई साथी बता रहे थे कि बिजली में interruption क्यों होता है। Transformer जल गए, इसकी वजह से गांवों में बिजली नहीं पहुंचती है। वे फरियाद करते हैं कि transformer जल गए हैं, तो 10 दिनों तक कोई नहीं आता है और 10 दिनों तक गांव बिजली के बिना रहता है। हमने यहां करीब 75,000 नए transformer लगाए, एक लाख किलोमीटर नयी wire लगाई, 200 से ज्यादा सब-स्टेशन बनाए और 15 लाख नए बिजली के खंभे लगाए। हमने पिछले 3 सालों में यह परिवर्तन किया है और वहां ज्योर्तिग्राम योजना के तहत हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। मैं बागड़ोदिया जी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने गुजरात की प्रशंसा की कि गुजरात ने दो लाइनें दीं- गांवों के लिए अलग लाइन, शहरों के लिए अलग लाइन। खेती के लिए अलग लाइन। वहाँ 24 घंटे लाइट रहेगी, तो गाँवों में बच्चे पढ़ेंगे, गाँवों में सभी नाना प्रकार के कुटीर उद्योग चलेंगे, गाँवों में लोग आराम से, चैन से रहेंगे, शहर

के लोग जो टीवी सीरियल 'कहानी घर-घर की' देखते हैं, तो गाँव की महिलाएँ भी बैठ कर 'कहानी घर-घर की' देख सकें। जब लाइट होगी, तभी यह होगा। इसलिए वहाँ यह सब परिवर्तित किया है।

दूसरी बात यह है कि इसके लिए पूरा पॉलिटिकल विल पॉवर चाहिए। हम पॉवर की बात कर रहे हैं, तो विल पॉवर चाहिए। जो बिजली की चोरी होती है, इसके लिए हम यह कानून ला रहे हैं। गुजरात में और सभी जगह, जैसे बताया गया कि छोटे-छोटे लोग चोरी नहीं करते हैं, बड़े-बड़े लोग चोरी करते हैं, बड़े-बड़े गुंडे लोग भी उसमें शामिल होते हैं। हमारे यहाँ कोई विजय भाई लाइट वाला ...(**व्यवधान**)... एक मिनट, मैं बोल लूँ, आप बाद में बोल लें ...(**व्यवधान**)... राजीव जी, प्लीज़ सुनिए ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): रूपाणी जी कह रहे हैं कि गुजरात में सब कुछ सही है, बिजली पूरे राज्य में मिल रही है, लोग 'कहानी घर-घर की' देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें भारत सरकार से कुछ नहीं चाहिए। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि उस दिन सौराष्ट्र में राजकोट में मैच हुआ था। सर, स्कोरबोर्ड तक नहीं चल रहा था, बिजली नहीं थी, जेनरेटर से उस क्रिकेट मैच का स्कोरबोर्ड चल रहा था ...(**व्यवधान**)... और ये कह रहे हैं कि बिजली है ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय कुमार रूपाणी: आप गलत बोल रहे हैं ...(**व्यवधान**)... राजकोट में 24 घंटे बिजली है ...(**व्यवधान**)... आप पॉलिटिकल बात मत कीजिए ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please, don't disturb him.

श्री विजय कुमार रूपाणी: राजीव जी, आज ऊर्जा मंत्री जी से पूछिए ...(**व्यवधान**)... देखिए, ऐसी बात मत कीजिए ...(**व्यवधान**)... राजकोट में लाइट थी, 24 घंटा मैच का प्रसारण हुआ था, आप भी थे ...(**व्यवधान**)... यह गतल बात है ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN: (PROF. P.J. KURIEN): Please continue.

श्री विजय कुमार रूपाणी: मैं यह कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल विल पॉवर चाहिए। जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे शहरों में जो गुंडे लोग हैं, वही लाइट का distribution करते हैं, वही उनकों वहाँ direct connection देते हैं और उनके पास से पैसा लेते हैं। ऐसे गुंडे लोगों से कड़क-से-कड़क हाथ से काम लेना चाहिए। मैंने बताया कि विजय भाई लाइटवाला यानी कि विजय भाई वहाँ बैठ कर लाइट का distribution कर रहा है, direct connection दे रहा है, विजय भाई उस इलाके में पैसा उगाहता है, फंड इकट्ठा करता है। मोहम्मद भाई लाइटवाला, युनूस भाई लाइटवाला। अब यह नहीं चलता है। गुजरात गवर्नमेंट ने कड़क हाथ से यह किया है। अभी इस कानून की बात हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए हर जिले में अलग पुलिस स्टेशन दे दिया गया है, पुलिस का स्टाफ भी उनको अलग दिया गया है, वहाँ रिटायर्ड आर्मी मैन भी रखे हैं। हम मानते

हैं कि जब टी एंड डी लॉस हम घटाएंगे, तभी यह बोर्ड अच्छा चलेगा और बोर्ड अच्छा चलेगा, तो quality of life अच्छी रहेगी। मैं आपको figure दे रहा हूँ, ख़ास राजीव जी को दे रहा हूँ। हमारे यहाँ टी एंड डी लॉस 40 परसेंट था, वह आज 18 परसेंट हो गया है। दूसरी बात यह है कि मीटर में जो manipulation होता है, तो हमने गुजरात में 15 लाख मीटर change किया है, 5 लाख लोगों के ऊपर केस किया है, चोरी को रोकने के लिए। उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। यह मतों की बात नहीं है। अगर आप मतों की सोचेंगे, तो यह काम कभी नहीं कर सकते हैं, यह नरेन्द्र मोदी ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकते। यानी पॉवरफुल ग्रिड चाहिए और पॉवरफुल लीड चाहिए। राजीव जी, यह लीड की बात आप नहीं समझेंगे ...(व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्ल: अगर इतनी बिजली है, तो आप राजस्थान को दे दीजिए न...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): No, please, take your seat ...*(Interruptions)*.

श्री रूद्रनारायण पाणि: राजस्थान क्या, पाकिस्तान को भी दिया जाएगा...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Please, take your seat.

श्री राजीव शुक्ल: इन्होंने मध्य प्रदेश से वादा किया था कि बिजली देंगे ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): रूपाणी जी खुद defend करेंगे, आप लोग बैठिए ...(व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्ल: चुनाव में नरेन्द्र मोदी जी ने वादा किया था कि मध्य प्रदेश को बिजली देंगे, लेकिन नहीं दी ...(व्यवधान)... राजस्थान को बिजली नहीं दे रहे हैं ...(व्यवधान)... और ये कह रहे हैं कि इनके पास बिजली ...(व्यवधान)... 'कहानी घर-घर की' देख रहे हैं, तो राजस्थान को दे दीजिए, मध्य प्रदेश को दे दीजिए ...(व्यवधान)... वहाँ जनता त्राहि-त्राहि कर रही है ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Please, take your seat ...*(Interruptions)*.

श्री विजय कुमार रूपाणी: आप सुनने की हिम्मत रखिए ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Why do you interfere? ...*(Interruptions)*. राजीव जी, टाइम नहीं है ...(व्यवधान)... The Minister will reply ...*(Interruptions)*.

5.00 P.M.

श्री राजीव शुक्ल: तो राजस्थान और मध्य प्रदेश को दे दीजिए न ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): ठीक है, आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... Rajeevji, you have made your point. आप लोग बैठिए ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव शुक्ल: सर, मोदी जी वैसे ही रूपाणी जी से बहुत खुश रहते हैं, इनको इतना अच्छा वचन बोलने की जरूरत नहीं है ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय कुमार रूपाणी: मैं यह मानता हूं कि राज्य बिजली बोर्ड डायनासोर की तरह बहुत बड़ा कारोबार नहीं संभाल सकते क्योंकि पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, उस को पता नहीं रहता है।

महोदय, जो अपने यहां जनरेशन होता है, उस में भी हंड्रेड परसेंट हो रहा है या कितना परसेंट हो रहा है, डिस्ट्रिब्यूशन में क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा हे, इस के लिए गुजरात में हम ने 7 कंपनियां बना दी हैं। उसका विभाजन कर दिया है, छोटी-छोटी कंपनियां बना दी हैं और उनका परफॉर्मेंस , उनका एनालिसिस ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Mr. Rupani, please wind up.

श्री विजय कुमार रूपाणी: सर सभी लोग बोले हैं, मैं भी बोल लूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): But, you are not talking about the Bill. You are talking about Gujarat only. What can I do? ...*(Interruptions)*... Mr. Rupani, time of your Party is over. ...*(Interruptions)*... The point is, all this time, you are talking about Gujarat, not about the Bill. You should know that.

SHRI RAJEEV SHUKLA: He is talking about Gujarat only. ...*(Interruptions)*...

SHRI SURENDRA LATH: He is interrupting him, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): No, please. Please sit down. You should not interrupt, Mr. Shukla. ...*(Interruptions)*... आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री विजय कुमार रूपाणी: महोदय, मैं बता रहा हूं कि हमने बिजली बोर्ड को 7 कंपनियों में रूपांतरित किया है। हमने 70 हजार कर्मचारियों को साथ लिया है, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ है। हम

ने सभी यूनियनों को साथ लेकर बिजली बोर्ड को 7 कंपनियों में रूपांतरित किया है। महोदय, आपको बताना चाहूंगा, सभी बाहर से पावर पर्चेज करते हैं, पहले जो कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने जो पावर पर्चेज की थी, हम ने उन पावर कंपनियों को बुलाया, आपको जानकर खुशी होगी कि हम ने उन के साथ बैठकर नेगोशिएशन किया और उन्होंने उस में 495 करोड़ रुपया कम कर दिया। हमारे यहां 495 करोड़ रुपए की बचत हुई। उस में हमारा जो 2200 करोड़ रुपए का घाटा था, वह हमने कम कर दिया। इस का मतलब यह है कि अगर राज्य के पावर कॉर्पोरेशन बोर्ड पारदर्शी बनें और ठीक तरह से काम करे तभी आगे सुधार होगा। महोदय, हम प्लांट लोड फैक्टर को 75 परसेंट तक ले गए जो पहले 40 परसेंट था। महोदय, हम मानते हैं कि पावर प्लांट की क्षमता बढ़े और जब वह 75 परसेंट तक बढ़ेगी तभी हमारे यहां क्वालिटी ऑफ पावर बढ़ेगी। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, एक्सलेंट पावर के लिए जो ए॰पी॰डी॰आर॰पी॰ है, उस में वह नुकसान का पैसा देते हैं। राजीव जी, आप यह बात सुनिए, उस में गुजरात ने 1050 करोड़ रुपया लिया है। इस का मतलब यह है कि हमारा कार्य एक्सलेंट है। इस वर्ष बजट में पैसा नहीं था, इसलिए उस ने 300 करोड़ रुपया अगले बजट में देने का वायदा किया है। इस तरफ गुजरात सरकार ने उन के पास से एक हजार करोड़ रुपया लिया है। यह हमारी परफॉर्मेंस है।

महादेय, आज टेरिफ रेट बढ़ने का कारण यह है कि कोयले का दाम बढ़ रहा है, फ्रेट का दाम बढ़ रहा है। जब टेरिफ रेट बढ़ेगा तो उस के आधार पर सभी बोर्डों का घाटा भी बढ़ सकता है। महादेय, जनरल ग्रिड से गुजरात को 208 मेगावाट बिजली मिल रही थी, लेकिन मंत्री जी आप ने वह महाराष्ट्र में डाइवर्ट कर दी है और हमारी 208 मेगावाट बिजली आप ने ले ली, यह ठीक नहीं है। इस कारण जो बिजली हम को 1 रुपए 67 पैसे के हिसाब से मिलती थी, आज वह 6 रुपए 50 पैसे में गुजरात को लेनी पड़ती है। इस कारण हम पर साढ़े 6 सौ करोड़ की जिम्मेदारी आ गयी है। महादेय, जो इम्पोर्टेट एल॰एन॰जी॰ गैस हम को मिलती थी, उसके लिए ''गेल'' ने एग्रीमेंट किया था, लेकिन अब गेल ने वह एग्रीमेंट सस्पेंड करने की बात की है जिस कारण हम को 700 करोड़ का और घाटा हो सकता है। हमारी आप से मांग है कि ''गेल'' हमारे पुराने एग्रीमेंट को रखे जिस से गुजरात को 700 करोड़ का घाटा न हो। हाल में गुजरात में हमने 25 हजार मेगावाट की प्लानिंग की है। हमने सेंट्रल प्रोजेक्ट, स्टेट प्रोजेक्ट, प्राइवेटाइजेशन के आधार पर टेंडर परचेज और सेंट्रल नॉर्म्स के आधार पर, रेग्यूलेटरी कमेटी के आधार पर यह सब टेंडरिंग किया है। इनर्जी में एक लाख करोड़ का एम॰ओ॰यू॰ हुआ है। आने वाले दिनों में गुजरात में ...(**समय की घंटी**)... सरप्लस पावर बने। इसी तरह पूरे देश में इस बिल के आधार पर आप कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई करें। जब हम अच्छी तरह से ऊर्जा प्रदान करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे, तभी देश का विकास होगा। मैं मानता हूँ कि इस बिल को पहले आने की आवश्यकता थी। आज यह बिल आ रहा है। तो पोलिटिकल विल ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Please wind up. समाप्त कीजिए।

श्री विजय कुमार रूपाणी: इसके ऊपर भी काम कीजिए, तो ठीक रहेगा। धन्यवाद।

MESSAGE FROM LOK SABHA—Contd.

The Central Road Fund (Amendment) Bill, 2007.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Central Road Fund (Amendment) Bill, 2007, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 16th May, 2007."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

The Electricity (Amendment) Bill, 2007—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Shri Rajniti Prasad. Please take only five minutes.

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): उपसभाध्यक्ष जी, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमें समय दिया।

महोदय, बहुत-सारे वक्ताओं ने यहां पर बोला है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलता हूं और हमारी समझ में आता है कि अभी रूपाणी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वहां 24 घंटे बिजली रहती है। तो इस पर पार्लियामेंट की एक कमेटी बनानी चाहिए, जो रिसर्च करे, वहां पर जाकर देखे कि क्या बात है? क्यों ऐसा होता है? हमें लगता है कि वहां पर 24 घंटे में कभी बिजली नहीं जाती है। तो क्या जब वहां दंगा हुआ था, उस वक्त भी बिजली नहीं गई थी? मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे बिजली, पूरे हिन्दुस्तान में, even in Parliament, even in Delhi, जहां हम रहते हैं, वहां भी 24 घंटे नहीं रहती, एक-दो मिनट इधर-उधर हो जाता है। अत: किसी के बारे में अगर ज्यादा कुछ कहना है तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, जिससे लगे कि आप उनके मामले को कुछ ज्यादा कर रहे हैं।